



करोड़ों रुपये बर्बाद, महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा पास हो रहे

विपक्ष के अड़ियल रवैये से संसद ठप

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में लगातार जारी हंगामे और गतिरोध ने देश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गर्माहट पैदा कर दी है।

भाजपा ने कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के साथियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे सुनियोजित तरीके से संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। इस असहयोगात्मक रवैये के कारण जहां एक तरफ करोड़ों रुपयों की जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देशहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा भी नहीं हो पा रही है।

मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा सदस्य संबित पात्रा ने कहा कि सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष का आचरण बेहद निराशाजनक रहा है।

हर संसदीय सत्र के संचालन पर



करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, ताकि देश के कोने-कोने से चुनकर आए सांसद अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठा सकें। परंतु, विपक्ष की जिद के कारण न तो प्रश्नकाल चल पा रहा है और न ही शून्यकाल का समुचित उपयोग हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजसे (संशोधन) बिल और रजिस्ट्रेशन आफ बर्थ एंड डेथ (संशोधन) बिल जैसे अहम विधायी सुधार बिना पर्याप्त चर्चा के ही पास कराने की स्थिति बन रही है, जिससे आम जनता जरूरी विधायी जानकारीयों से वंचित हो रही है।

पेपर लोक और राम मंदिर के संतों पर दोहरे मापदंड का आरोप: भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते

हुए उस पर चुनिंदा आक्रोश दिखाने का भी आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लोक और भर्ती घोटालों पर पार्टी के नेता पूरी तरह चुप्पी साध लेते हैं, जबकि अन्य जगहों पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है।

उन्होंने झारखंड और कर्नाटक का हवाला देते हुए राहुल गांधी और उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही, संसद परिसर में राम मंदिर के दान को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन पर भी भाजपा ने गहरी नाराजगी जताई। पात्रा ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति को साधु के वेश में चोर के रूप में चित्रित करना और उसे घसीटना देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थान और संत समाज का अपमान है।

इस तरह के कृत्यों से धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।



रायपुर। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज का जीवन समरसता, समानता, भक्ति, श्रम और सामाजिक न्याय का अमर संदेश है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने सदियों पहले थे। संत रविदास ने समाज को ऊंच-नीच, भेदभाव और छुआछूत से ऊपर उठकर मानवता, समान अधिकार और आध्यात्मिक चेतना का मार्ग दिखाया। यही मार्ग विकसित, समरस और सशक्त भारत की आधारशिला है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कलश वंदन महाअभियान के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही।(विस्तृत समाचार पेज-8 पर)

मोदी के वीडियो हटाने पर मेटा को संसदीय समिति का अल्टीमेटम

नई दिल्ली। कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने को लेकर मेटा के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग से सार्वजनिक माफ़ी की मांग की है। साथ ही, समिति ने चेतावनी दी है कि



अगर कंपनी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो उसे सेफ़ हार्बर प्रोटेक्शन (सुरक्षित दायरे का संरक्षण) का लाभ गंवाना पड़ सकता है। समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, पैन्ल के चेयरमैन निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के सामने दो स्पष्ट मांगें रखी हैं। दुबे ने कहा कि हमारी कमिटी ने दो बातें कही हैं और साफ़ तौर पर कहा है कि ज़ुकरबर्ग को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ज़ुकरबर्ग माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उनसे सेक्शन 79 के तहत मिलने वाली सेफ़ हार्बर सुरक्षा वापस ले ली जानी चाहिए। पीएम का वीडियो हटाए जाने को गंभीर मामला बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना देश की अस्थिर करने की कोशिश को दिखाती है।

उपचुनाव नतीजों पर प्रियंका बोलीं भाजपा से ऊब चुके हैं लोग

नयी दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने विधानसभा उपचुनावों के नतीजों को लेकर मंगलवार को दावा किया कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से ऊब चुके हैं और देश में क्या हो रहा है, इसे समझने लगे हैं। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा,



“साफ है कि लोग भाजपा से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। लोग समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। मेरी समझ है कि यह शुरुआत है।” यह पूछे जाने पर इन नतीजों का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कोई असर होगा, तो प्रियंका गांधी ने कहा, आगे देखेंगे। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भाजपा को पराजित किया। इससे पहले इस सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गूडकार ने भाजपा के उपचुनाव में भाजपा को पराजित किया। भाजपा गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर यह सीट अपने पास बरकरार रखी।

पंजाब कांग्रेस में सियासी उबाल इस्तीफा नहीं दूंगा : राजा वडिंग

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी कलह के बीच, राज्य इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पद छोड़ने की बात से इनकार किया। साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें बदलने का फैसला



भी करता है, तो भी वह संगठन के लिए काम करते रहेंगे। बरिंडा में कांग्रेस के हर बूथ, कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम के दौरान, पंजाब के प्रभारी एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल की मौजूदगी में वडिंग ने पत्रकारों से कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। वडिंग ने आगे कहा कि अगर पार्टी आलाक़मान मुझे बदलने का फैसला करता है, तो भी मैं संगठन को मजबूत करने के लिए काम करता रहूँगा। लुधियाना के सांसद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चबी के समर्थकों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों के दौरान उनके पक्ष में नारे लगाए, जिससे राज्य इकाई के भीतर गुटबाज़ी का तनाव खुलकर सामने आ गया।

तृषा पर टिप्पणी, उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार

चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी का स्वागत किया। स्टालिन ने तंजावुर में डीएमके की एक रैली के दौरान एक्स्ट्रेम तृषा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवाद खड़ा



कर दिया था। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कहा कि स्टालिन के साथ ऐसा ही होना था। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म का अपमान किया, उसे एक महिला के बारे में घटिया और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ ऐसा ही होना था। तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य मीडिया कोऑर्डिनेटर नारायणन तिरुपति ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि कोई तय करेगा कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है या महिलाओं की गरिमा! यह विवाद तंजावुर में कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर डीएमके के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ, जहाँ स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर तीखा हमला किया।

केजरीवाल पीएम आवास के लिए मार्च करते हुए दिल्ली में रोके गए

नयी दिल्ली। देश में ई-20 पेट्रोल की बिक्री के खिलाफ 2.30 लाख से अधिक जापनों को सौंपने के लिए प्रधानमंत्री आवास की ओर मंगलवार को करीब 100 लोगों के साथ मार्च कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं को दिल्ली पुलिस ने



फिरोजशाह मार्ग पर रोक लिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जैस्मीन शाह और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ फिरोजशाह मार्ग पर ही धरने पर बैठ गए। आप ने देश भर के लोगों से एकत्र जापनों को सौंपने के लिए लगभग 100 लोगों के साथ मार्च शुरू किया था। ये जापन सरकार की ई-20 पेट्रोल को बढ़ावा देने वाली नीति के खिलाफ हैं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एथनॉल-मिश्रित ईंधन का वाहन मालिकों पर बुरा असर पड़ रहा है। केजरीवाल ने मार्च से पहले समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी देश भर के लोगों द्वारा हस्ताक्षरित 2.30 लाख से अधिक जापन लेकर जा रही है और उन्होंने सरकार से करोड़ों वाहन मालिकों की चिंताओं पर संज्ञान लेने की अपील की।

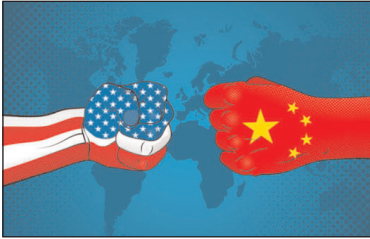
अमरीका ने चीन को अपने ही प्रभुत्व को चुनौती देने में मदद की

सुदीपो मुंडले

मिखाइल गोर्बाचेव के 25 दिसम्बर, 1991 को दिए गए इस्तीफे ने सोवियत साम्राज्य के पतन पर मुहर लगा दी थी। अमरीका उस वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवस्था का एकमात्र सर्वोच्च नेता बन गया, जिसे उसने और उसके सहयोगियों ने 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में स्थापित किया था। लेकिन उससे 20 साल पहले, 1971 में, जब अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन व हेनरी किंसिंग्टन ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पी.आर.सी.) के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए चीन का दौरा किया, तो अमरीका ने खुद ही एक नई वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवस्था के उद्भव का रास्ता साफ कर दिया था, जिसमें चीन आगे चलकर अमरीका के वर्चस्व को चुनौती देगा।

पी.आर.सी. को चीन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देकर, निक्सन-किंसिंजर मिशन ने कई दरवाजों में से पहला दरवाजा खोला, जो अंततः चीन को पश्चिम के प्रभुत्व वाली वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में पूर्ण प्रवेश की ओर ले गया। निक्सन की यात्रा के बाद, पी.आर.सी. ने 1971 में संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ताइवान स्थित रिपब्लिक ऑफ चाइना (आर.ओ.सी.) की जगह ले ली। 1980 तक, पी.आर.सी. ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) और विश्व बैंक में भी आर.ओ.सी. को प्रतिस्थापित कर दिया था, जो अमरीका के नेतृत्व वाली वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के 3 स्तंभों में से 2 हैं। 11999 में चीन और अमरीका ने एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बाजार पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर

किए। दिसम्बर 2001 में चीन डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल हो गया। तीन दशकों की इस यात्रा के दौरान चीन के भीतर भी बहुत कुछ बदल गया। 1976 में माओत्से तुंग के बाद सत्ता में आए दंग शियाओपिंग ने 1978 में ‘गाइडेड काइफेंग’ यानी ‘सुधार और खुलापन’ कार्यक्रम शुरू किया। इसके कारण चीन की आर्थिक प्रणाली में मौलिक परिवर्तन आया और नई चुनौतियां भी सामने आईं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और उसके संस्थानों तक बढ़ती पहुंच ही वह सहारा बनी, जिसने चीन को इन व्यापक आंतरिक परिवर्तनों से निपटने और निर्यात में सफलता हासिल करने के लिए खुद को मजबूती से स्थापित करने में सक्षम बनाया। इसने आक्रामक व्यापारिक नीतियां अपनाईं, विशेष रूप से अवमूल्यित (कम आंकी



गई) मुद्रा।

2001 तक, जब चीन डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल हुआ, तो वह पहले से ही ‘दुनिया की फैक्ट्री’ के रूप में उभर चुका था। लेकिन वह हमेशा के लिए केवल निर्यात-आधारित रणनीतियों पर निर्भर नहीं रह सकता था। निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता, उच्च-बचत और उच्च-निवेश वाली विकास रणनीति से घरेलू खपत-संचालित रणनीति की ओर जाने का

उसका प्रयास (जहां निवेश और बचत दरें कम होती हैं) सफल नहीं हुआ। चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात पर ही निर्भर बनी रही। अब पूंजी निर्यात की रणनीति भी अपनाई जा रही है। शी जिनपिंग द्वारा 2013 में शुरू की गई बैल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बी.आर.आई.) के तहत, चीन की अतिरिक्त बचत का उपयोग लगभग 150 (मुख्यतः) विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विशाल पोर्टफोलियो को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें चीन की अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण की क्षमता का लाभ उठाया जा रहा है।

क्रय शक्ति समता के मामले में चीन पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और संभावना है कि यह

कुछ दशकों के भीतर पारंपरिक जी.डी.पी. के मामले में भी अमरीका को पीछे छोड़ देगा। लेकिन आर्थिक मोर्चे के अलावा, चीन अब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अमरीकी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) तकनीकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की एक प्रमुख उदाहरण है। यहां, डीएस, क्रैक, किमी और अन्य, जैसे ओपन-सोर्स चीनी ए.आई. मॉडल, चैटजीपीटी, जेमिनी और क्लाउड जैसे तुलनीय अमरीकी संस्करणों की तुलना में एक-तिहाई से 10वें हिस्से की कम कीमत पर उपलब्ध हैं, ठीक उसी तरह जैसे चीनी इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) ने अन्य ई.वी. को कीमत के मामले में पीछे छोड़ दिया है।

ऐसा कैसे हो रहा है? दशकों से, हजारों चीनी छात्र प्रमुख अमरीकी

विश्वविद्यालयों से स्नातक हुए हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एस.टी.ई.) में विशेषज्ञता प्राप्त की है। हालांकि कुछ यहीं रुक गए लेकिन अधिकांश चीन लौट आए और चीनी प्रयोगशालाओं और उद्यमों में प्रतिद्वंद्वी उत्पादों के उत्पादन में लगे हुए हैं। साथ ही, कई अमरीका शिक्षित विशेषज्ञ चीनी विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जिससे स्वदेशी रूप से अगली पीढ़ी के विशेषज्ञों का उत्पादन हो रहा है। चीन जिस तीसरे मोर्चे पर अमरीकी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, वह है वैश्विक वित्तीय प्रणाली। 2015 में चीन ने डॉलर आधारित स्विफ्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में रेनमिनबी आधारित चीनी सीमा पार अंतरबैंक भुगतान प्रणाली (सी.आई.पी.एस.) शुरू की। इसकी पहुंच अभी भी सीमित है।

डोंगरगढ़ भाजपा में इस्तीफों का सिलसिला जारी नई नियुक्तियों के अगले ही दिन मंडल सह संयोजक पंकज अग्रवाल ने छोड़ी जिम्मेदारी

डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ भाजपा में अंदरूनी असंतोष थमता नजर नहीं आ रहा है। 111 कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे, फिर 25 नेताओं के इस्तीफे और उसके बाद लगातार सामने आ रहे इस्तीफों के बीच अब एक और नाम जुड़ गया है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की नई जिला कार्यकारिणी घोषित होने के अगले ही दिन डोंगरगढ़ मंडल के सह संयोजक पंकज अग्रवाल ने पार्टी की जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। इससे संगठन के भीतर चल रही हलचल एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

पंकज अग्रवाल ने भाजपा जिलाध्यक्ष को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा है कि वे भाजपा आईटी सेल में कार्यरत हैं, लेकिन व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों से संगठन को अपेक्षित समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी



कारण उन्होंने भाजपा आईटी सेल की जिम्मेदारियों और पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए अवसर, मार्गदर्शन और विश्वास के लिए आभार भी व्यक्त किया है तथा भविष्य में पार्टी के प्रति सम्मान बनाए रखने की बात लिखी है।

हालांकि, इस्तीफे में व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है जब डोंगरगढ़ भाजपा पहले से ही लगातार संगठनात्मक संकट से जूझ रही है। हाल के दिनों में 111 कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे, फिर 26 नेताओं के

इस्तीफे, पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष सुमित मिश्रा के इस्तीफा और फिर उसे वापस लेने के घटनाक्रम ने संगठन की अंदरूनी खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि नई नियुक्तियों के बीच लगातार सामने आ रहे इस्तीफे संगठन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। हालांकि, पंकज अग्रवाल ने अपने इस्तीफे में किसी पदाधिकारी या संगठन पर कोई आरोप नहीं लगाया है और केवल निजी कारणों का हवाला दिया है। लगातार हो रहे इस्तीफों ने डोंगरगढ़ भाजपा की संगठनात्मक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इन घटनाक्रमों को किस तरह संभालता है और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए क्या कदम उठाता है।

35 की जगह 20 किलो चावल देने का आरोप

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 10 मार्च और 7 अप्रैल 2026 को राशन वितरण के दौरान अनियमितता बरते जाने का पता चला।

धमतरी। मगरलोड ब्लॉक में करेली बड़ी गांव है। यहां ग्रामीणों ने उचित मूल्य राशन दुकान में तय मात्रा से कम राशन दिए जाने का आरोप लगाया है। कई ग्रामीणों ने पुलिस चौकी करेली बड़ी में लिखित आवेदन देकर राशन दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि 35 किलो चावल निर्धारित होने के बाद भी कई महीनों तक केवल 20 किलोग्राम चावल ही दिया गया। ग्रामीणों ने सरकारी राशन के गबन और हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में



आवेदन दिया है। इस आवेदन में कहा गया है कि करेली बड़ी की उचित मूल्य दुकान में मार्च से जून 2026 के बीच कई राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम चावल दिया गया। सभी को 35 किलो चावल की जगह 20 किलो चावल द दिया गया।

शिकायत में जेट्टन बाई, झरिहारिन साहू, इंदु साहू, हेमिन बाई, गामिनी साहू, वासुकी साहू,

भारती राव, प्रभा बाई निषाद, सुशीला पटवा, जमुना बाई साहू, सेवती यादव, दुलारी बाई साहू, प्रीति सेन, रूपा, मधु यादव, राजो बाई यादव, सपना भाट सहित कई हितग्राहियों के राशन कार्ड नंबर और संबंधित महीनों का जिक्र किया गया है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 10 मार्च और 7 अप्रैल 2026 को राशन वितरण के दौरान गंभीर अनियमितता का पता चला। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि यह मामला सिर्फ कम राशन वितरण तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सरकारी राशन में गबन, सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और पात्र हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी की गंभीर मामला है।

ग्रामीणों ने पुलिस से अपराध दर्ज कर जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे

वितरण रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, ऑनलाइन एंट्री और वास्तविक वितरण का मिलान कराया जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। शिकायतकर्ता करेली बड़ी निवासी ढालचंद निषाद ने आरोप लगाया कि उन्होंने लगातार खाद्य विभाग में इस अनियमितता की शिकायत की, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि शिकायत के बाद विभागीय जांच टीम भी मौके पर पहुंची थी और जांच की प्रक्रिया पूरी की गई, इसके बावजूद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

ढालचंद ने कहा कार्रवाई में हो रही देरी पूरे मामले को संदेह के घेरे में खड़ा करती है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

स्टाइपेंड बढ़ाने मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों ने दिया धरना



स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित

जगदलपुर। डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज में इंटर्न डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को काम बंद कर एक दिवसीय हड़ताल की। इंटर्न डॉक्टरों की मांग है कि उनका मासिक स्टाइपेंड 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाए। हड़ताल के चलते मेकांज की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई।

इंटरन डॉक्टरों के अनुसार छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में इंटरन डॉक्टरों को 40 से 45 हजार मासिक स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन इसकी तुलना में छत्तीसगढ़ के इंटरन डॉक्टरों को सरकार बेहद कम स्टाइपेंड दे रही। इससे पहले भी इंटरन डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन

सौंपा था, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई।

वहीं इंटरन डॉक्टरों की हड़ताल का सीधा असर मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिला। मेकांज की व्यवस्था नियमित डॉक्टरों के भरोसे रही। मेडिकल कॉलेज के पार्किंग स्थल में इंटरन डॉक्टरों ने धरना देकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग दोहराई। जूनियर डॉक्टरों ने भी इंटरन डॉक्टरों को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और इंटरन डॉक्टरों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार से मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही

स्पोर्ट्स टीचर भर्ती को लेकर फूटा गुस्सा

दुर्ग में स्पोर्ट्स टीचर्स भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे.

दुर्ग। प्रदेश भर से दुर्ग में जुटे और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मिलने पहुंचे। शिक्षकों का आरोप है कि 3000 शिक्षकों की भर्ती में स्पोर्ट्स टीचर का एक भी पद शामिल नहीं किया गया है, जिससे हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है।

अभ्यर्थी ने बताया कि व्यायाम शिक्षक का पद हटा दिया गया। हम उसकी मांग करने आए हैं। पहले तो 300 पद के लिए विज्ञापन निकला तो हम सभी तैयारी में जुट गए। फिर 154 पद की बात आई, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो एक भी व्यायाम शिक्षक का पद नहीं है। मंत्री कहते हैं कि हमें खिलाने वाले नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक चाहिए।

अभ्यर्थी ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 में यह लागू कर दिया है कि प्राथमरी लेवल से फिजिकल एजुकेशन जरूरी है, बुक भी प्रोवाइड कर दिए हैं। लेकिन व्यायाम शिक्षक ही नहीं हैं। छत्तीसगढ़ से कॉमनवेल्थ गेम में केवल ज्ञानेश्वरी यादव ने ही मेडल लाया है। लेकिन यह



समझना जरूरी है कि यह मेडल कैसे मिला। मेडल लाने के लिए क्या जरूरी है, इसको भी समझना होगा, इसका कोई समाधान नहीं है। हमारा बेस लेवल ही खराब है। स्कूल में कॉलेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर की कमी है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर साल व्यायाम शिक्षक का पद निकले। व्यायाम शिक्षक के पदों पर अंतिम भर्ती वर्ष 2019 में हुई थी। इसके बाद अब तक कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। साल 2023 से लगातार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। शिक्षा मंत्री ने मुलाकात के

दौरान 2027 में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन चाहते हैं।

स्पोर्ट्स टीचरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि पिछले छह महीनों से वे लगातार विभाग और मंत्रालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

ग्राहक बनकर पहुंचा शातिर चोर, 4.45 लाख की सोने की इयररिंग लेकर फरार

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राहक बनकर पहुंचे शातिर चोर ने दिनदहाड़े ज्वेलर्स दुकान में हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

पूरा मामला नगरी थाना क्षेत्र के नगी बाजार स्थित नवकार ज्वेलर्स का है। बताया जा रहा है कि आरोपी बड़ी ही चालाकी से दुकान में दाखिल हुआ और सोने की ईयर रिंग दिखाने की बात कहने लगा। दुकानदार को क्या पता था कि ये ग्राहक नहीं बल्कि

एक शातिर चोर है। इसी बीच जैसे ही दुकानदार का ध्यान थोड़ा भटक आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर काउंटर पर रखे 9 नग सोने के ईयर रिंग पर हाथ साफ कर दिया और पलक झपकते ही दुकान से फरार हो गया, जब दुकान के मालिक ने काउंटर पर रखे जेवरात को गिना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में आसपास तलाश की गई, लेकिन तब तक आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो चुका था। बताया जा रहा है कि चोरी हुए जेवरात की कुल कीमत 4 लाख 45 हजार रुपये आंकी गई

है। घटना के बाद पीड़ित दुकान मालिक ने तत्काल नगरी थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर नगरी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और दुकान में लगे श्रृङ्खल फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद नगरी के व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल है। अब देखना होगा कि नगरी पुलिस इस शातिर चोर को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है।

सड़क हादसे में आप के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष घायल, बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा

जांजगीर-चांपा। जिले में नेशनल हाईवे पर सोमवार को सड़क हादसे में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ, जब वे अकलतरा से बिलासपुर की ओर जा रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रास्ते में अचानक सामने आए एक बाइक सवार युवक को बचाने के प्रयास में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में अभिषेक मिश्रा को चोटें आई हैं। घटना के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए बिलासपुर भेजा गया। फिलहाल अभिषेक मिश्रा की स्थिति पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चिंता का माहौल है। पुलिस ने भी घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

पखांजूर में स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली का विरोध

कांकेर। पखांजूर मरोड़ा साप्ताहिक बाजार में बांटे मंडल कांग्रेस कमेटी ने महंगी बिजली और स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। बाजार पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों से हस्ताक्षर करवाकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली की बढ़ती दरों और स्मार्ट मीटर लगाए जाने से आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। उनका दावा है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बांटे मंडल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ बड़ाई ने कहा कि लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करती है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला वापस नहीं लिया और बिजली दरों में उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी।

जुलाई में अगस्त की पैकेजिंग वाला सामान सील

खैरागढ़। खैरागढ़ में जुलाई माह में अगस्त माह की पैकेजिंग की खाद्य सामग्री बेचने का मामला सामने आया है। रिटेल स्टोर में जुलाई माह के दौरान पोहा बेचा जा रहा था, जिस पर अगस्त 2026 की पैकेजिंग डेट और बैच नंबर अंकित था। मामला सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 38 पैकेट पोहा सीज कर दिए हैं। 31 जुलाई को खरीदारी के लिए पहुंचे एक ग्राहक की नजर शांति कंपनी के पोहे के पैकेट पर छपी पैकेजिंग डेट पर पड़ी। पैकेट पर अगस्त 2026 की पैकेजिंग डेट दर्ज थी, जबकि उस समय जुलाई का महीना चल रहा था। भविष्य की तारीख देखकर ग्राहक हैरान रह गया। इसके बाद ग्राहक ने कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए उसने पूरे मामले की शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन से की। शिकायत मिलते ही अधिकारी सिद्धार्थ पांडे अपनी टीम के साथ शुभम के माट पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित ब्रांड के सभी पैकेटों की जांच की।

भैसवार गांव के दो बेटों ने नेपाल में लहराया तिरंगा

कोरिया। कोरिया जिले के छोटे से गांव भैसवार के दो साधारण परिवारों के युवाओं ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मंगलेश कुमार साहू और परमेश्वर सिंह ने नेपाल में आयोजित 11वीं इंडो-नेपाल इंटरनेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास बात यह रही कि भारत ने इस प्रतियोगिता में पूरे 10 साल बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारतीय टीम के राइट स्ट्राइकर मंगलेश कुमार साहू ने प्रतियोगिता के अहम मुकाबले में भारत की ओर से पहला गोल कर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार खेल और आक्रामक प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट स्ट्राइकर का खिताब दिया गया। बेस्ट स्ट्राइकर का अवार्ड मिला है। गोल्ड मेडल जीतकर आए हैं। मुझे परिजनों और विधायक से सहयोग मिला। अब थाईलैंड जाएंगे। बचपन से सपना था कि इंटरनेशनल खेलूं। मैं गरीब परिवार से हूं, लेकिन खेलना जारी रखा। पहले जिला, फिर संभाग, फिर स्टेट लेवल पर हुआ।

धमतरी में पहली बार गंगा महाआरती, बनारस की तर्ज पर

धमतरी। सावन का पवित्र महीना धमतरी के लिए एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल लेकर आया। सावन सोमवार के पहले दिन पहली बार महानदी के चित्रोत्पला तट स्थित रुद्रेश्वर घाट पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन हुआ। बनारस की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की तर्ज पर आयोजित इस कार्यक्रम ने हजारों श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। शाम ढलते ही पूरा घाट दीपों की रोशनी, वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और घंटियों की गूंज से भक्तिमय हो उठा। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच जब विशाल दीपदान हाथों में लेकर गंगा महाआरती शुरू हुई तो पूरा घाट भक्ति से भर उठा। श्रद्धालु हाथ जोड़कर आरती में शामिल हुए और हर-हर महादेव तथा गंगा मैया के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। आरती के समापन पर आतिशबाजी ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। गंगा आरती देखने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि धमतरी में इस तरह का आयोजन पहली बार देखने को मिला। सावन के पहले सोमवार को इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

अबुझमाड़ के गांवों तक पहली बार पहुंचे तेन्दूपता फड़

नारायणपुर। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरे अबूझमाड़ में रहने वाले आदिवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार जंगल से मिलने वाली लघु वनोपज रही है। इनमें तेन्दूपता, जिसे स्थानीय लोग %हरा सोना भी कहते हैं, ग्रामीणों की सालाना आय का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। एक समय ऐसा भी था, जब इस हरे सोने पर भी नक्सलियों का प्रभाव था। ग्रामीण अपनी इच्छा से तेन्दूपता नहीं बेच पाते थे। लेकिन अब नक्सलमुक्त होने के बाद अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और तेन्दूपता आसानी से संग्रह कर बेच पा रहे हैं। कई बार संग्रहण केंद्र तक पहुंचने के लिए जंगल पहाड़ी इलाके में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और रास्ते में नक्सली गतिविधियों का डर भी बना रहता था- ग्रामीण 31 मार्च 2026 के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। नक्सल प्रभाव कम होने के साथ ही अबूझमाड़ में विकास कार्य हो रहे हैं। साल 2026 में यहां पहली बार तेन्दूपता संग्रहण के लिए नए फड़ खोले गए हैं।

राज्य स्तरीय खेलों में दंतेवाड़ा का परचम

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के खिलाड़ियों ने रायपुर में हुई राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जिले का नाम रोशन किया है। इन खिलाड़ियों ने कुल 69 पदक अपने नाम किए। इनमें 33 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। दंतेवाड़ा जिले से कुल 70 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय खेल में हिस्सा लिया। इनमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों के विद्यार्थी, खेल परिसर जावंगा और इंडोर स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ी शामिल थे। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, बालोद, भाटापारा, सारंगढ़, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, कांकेर,



कोंडागांव, कोरबा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद दंतेवाड़ा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की। कड़ी अभ्यास और सही मार्गदर्शन

से उन्हें यह सफलता मिली। छात्रावासों और खेल परिसरों में मिल रही बेहतर खेल सुविधाओं से भी खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। दंतेवाड़ा जिले के खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर जिला प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग,

प्रशिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद से बस्तर में लगातार खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस्तर पंडुम का भी आयोजन उसी कड़ी का हिस्सा है।

सब इंजीनियर के घर से लाखों के सोने-चांदी की चोरी

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित कोणाक रेसिडेंस कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। नेशनल हाईवे विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर रितेश सिंह के सूनू मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने करीब 20 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया।

जानकारी के अनुसार, रितेश सिंह परिवार सहित काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी गए थे। इसी दौरान शनिवार और रविवार की दरमियानी रात चोरों ने उनके मकान के मुख्य गेट का सेंट्रल लॉक तोड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने घर के सभी



कमरों की तलाशी ली और अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपी घर में लगे सीसीटीवी सिस्टम का

डीवीआर भी अपने साथ ले गए, ताकि पुलिस को कोई फुटेज न मिल सके। घटना की जानकारी मिलने पर रितेश सिंह ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के

खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है।

संक्षिप्त समाचार

सीएम साय का बड़ा ऐलान, माघ पूर्णिमा पर रहेगी सरकारी छुट्टी



मंगलवार को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि माघ पूर्णिमा को अब सरकारी छुट्टी रहेगी। इस दिन मास मंदिरा का विक्रय भी बंद रहेगा। सीएम ने यह भी घोषणा की कि राज्य अलंकरण में एक पुरस्कार संत रविदास के नाम पर दिया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, नया रायपुर में एक प्रमुख चौक का नाम संत रविदास के नाम पर करेंगे। इसके अलावा उनके संदेशों को विधानसभा में अंकित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे। ये अगले साल फरवरी 2027 तक कार्यक्रम चलेगा।
निगम में प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने आयुक्त मिश्रा ने अधिकारियों को सौंपा अतिरिक्त प्रभार

रायपुर। रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां लागू कर दी गई हैं। जारी आदेश के अनुसार उपायुक्त जागृति साहू को उनके वर्तमान कार्यों के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग (जाति प्रमाण पत्र शाखा) के उपायुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं उपायुक्त जसदेव सिंह बाबर का उदके मौजूदा दायित्वों के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के उपायुक्त और जोन क्रमंक-2 के चेक संबंधी कार्यों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा प्रभारी उपायुक्त संगीता साहू को उनके वर्तमान कार्यों के साथ जनसूचना अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।

कृषि विधि में रिक सीटों पर प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कृषि अभियांत्रिकी संकाय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय चरण ऑनलाइन काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम-2026 के अनुसार संपन्न की जाएगी। द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया 1 से 10 तक संचालित रहेगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट आईजीकेवी.एसी.ईन पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से साइन अप कर लॉग इन करें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करें। पात्र अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची 14 अगस्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। द्वितीय चरण की काउंसिलिंग पीईटी- के अभ्यर्थियों के लिए 17 अगस्त , जेईई-मेन्स- के अभ्यर्थियों के लिए 18 अगस्त , 12वीं (गणित समूह) के मेरिट अभ्यर्थियों के लिए 19 अगस्त तथा अन्य राज्य के पात्र अभ्यर्थियों के लिए से स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कृषि अभियांत्रिकी संकाय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित की जाएगी।

डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में मिला अज्ञात युवती का शव, हत्या की आशंका

रायपुर। खमतराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में मंगलवार को एक अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है और उसके गले में रस्सी का फंदा कसा हुआ था तथा मुंह में कपड़ा टूंसा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही खमतराई थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है लेकिन इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

आम आदमी पार्टी में पूर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की हुई घर वापसी

रायपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी छोड़कर गए जसवीर सिंग चावला जी जो पूर्व में कोषाध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री के महत्वपूर्ण पदों पर थे तथा जिन्होंने कुछ दिन पूर्व नाराजगी की वजह से पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया था आज पुनः उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए संगठन में अपनी वापसी दर्ज कराई, उनके साथ अनेक साथियों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी में पुनः वापसी की।

कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल , प्रदेश महासचिव वदूद आलम, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय,प्रदेश उपाध्यक्ष

राजधानी/छत्तीसगढ़

खेल मंत्री साव की बड़ी घोषणा, प्रदेश में हॉकी लीग का होगा आयोजन

रायपुर। हाल ही में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स में छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव के नायाब प्रदर्शन के बाद मीडिया से रू-बरू होते हुए खेल मंत्री अरुण साव ने प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विकास का खाका पेश करते हुए बताया कि तीरंदाजी में प्रदेश को अग्रणी बनाने के लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। इसके अलावा जल्द ही हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा।

खेल मंत्री अरुण साव ने खेल सचिव यशवंत कुमार की मौजूदगी में प्रदेश में खेल अधोसंरचनाओं के विकास की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य को तीरंदाजी में देश में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. खेल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से सेक्टर-3 नवा रायपुर अटल नगर में 67 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल आर्चरी एकेडमी की स्थापना की जा रही है. इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण को 13.47 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आबंटन किया गया है।

उन्होंने बताया कि सम्मिलित अधोसंरचनात्मक विकास के लिए एनटीपीसी, एनआरएएनवीपी एवं

डीएसवाईडब्ल्यू के मध्य अकादमी निर्माण के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।

मंत्री ने बताया कि इसी तरह जशपुर जिले में भी लगभग 18 करोड़ लागत की आर्चरी अकादमी की स्थापना की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य जारी है. इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर-28 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। फेज-1 में 114.05 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान एव स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका निर्माण कार्य प्रगतिरत है. वहीं फेज 2 के लिए 94.69 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि जशपुर एवं रायगढ़ जिले में वृहद इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्वीकृति जारी की गई है। कुनकुरी जशपुर में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 64 करोड़ रुपए और रायगढ़ में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 92 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जो प्रक्रियाधीन है।

बस्तर ओलम्पिक का जिक्र करते हुए खेल मंत्री अरुण साव ने बताया कि वर्ष

खेलों के विकास के लिये 6 जिलों में जिला खेल अधिकारियों की होगी नियुक्ति

रायपुर। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की बढ़ती धाक के मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिये कमर कसते हुए आज उपमुख्यमंत्री व खेल मंत्री अरुण साव ने बड़ा फैसला लेते हुए सुबे के छह नए जिलों में जिला खेल अधिकारी के पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दे दी गई है। इन नियुक्तियों से स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों के संचालन और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जिन जिलों में जिला खेल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी उनमें मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सक्ती, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही शामिल हैं।



गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और सरकार खेल अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर और जशपुर में उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जिन जिलों में जिला खेल अधिकारियों का निर्माण कार्य जारी है, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी। खेल मंत्री साव ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन की शुरुआत की है, जिसके लिए

100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें प्रशिक्षण देना और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना है।14 प्रशिक्षकों को आधुनिक खेल प्रशिक्षण के लिए पटियाला भेजा गया है, जहां वे नवीनतम तकनीकों और खेल विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा, जिससे प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा और खेल संस्कृति को और मजबूती मिलेगी।

मंत्री राजवाड़े की पहल से सूरजपुर जिले को मिली 5 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति

■ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पोषण और बाल विकास सेवाओं का हो रहा निरंतर विस्तार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में महिला एवं बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की विशेष पहल और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप सूरजपुर जिले में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के युक्तियुक्तकरण एवं संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन की स्वीकृति के आधार पर लिया गया है। इससे दूरस्थ एवं जरूरतमंद क्षेत्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सेवाएं और अधिक सुलभ हो सकेंगी।

स्वीकृत केंद्र ओड़ुगी और भैयाथान परियोजना के अंतर्गत



डगमलापारा (चेंद्रा सेक्टर),भुंडा (मोहरसोप सेक्टर), झाडूडीह (चेंद्रा सेक्टर),पण्डोपारा (चेंद्रा सेक्टर),बगईहापारा (दर्रापारा सेक्टर) पर संचालित होंगे।

इन क्षेत्रों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रों की स्वीकृति दी गई है। विभागीय आदेश के अनुसार कुछ पूर्व संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का युक्तियुक्तकरण कर उन्हें अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अधिक से अधिक हितग्राहियों तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है।

संचालनालय ने जिला प्रशासन एवं संबंधित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी नवस्वीकृत आंगनबाड़ी

केंद्रों का संचालन 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया जाए। साथ ही पोषण ट्रैकर एवं आईसीडीएस पोर्टल पर आवश्यक अद्यतन, कार्यकर्ता एवं सहायिका पदों की व्यवस्था तथा भवन एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को सुपोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सूरजपुर जिले में नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति से दूरस्थ बस्तियों में रहने वाले बच्चों और माताओं को सीधा लाभ मिलेगा तथा कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी।

विभागीय जानकारी के अनुसार इन नए केंद्रों की स्वीकृति के बाद सूरजपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल संख्या 2086 हो जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार की समावेशी विकास, मातृ-शिशु कल्याण तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



2024 से बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। बस्तर ओलम्पिक के 2 संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए। इन प्रतियोगिताओं से प्रतिभावान खिलाड़ियों का चिन्हित किया गया है। वर्ष 2024 में 1.65 लाख पंजीयन एवं वर्ष 2025 में 3.91 लाख पंजीयन प्राप्त हुए। 11 खेल विधाओं में प्रतिभागिता का आयोजन किया गया. विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले बस्तर ओलंपिक 2024 में 13 खिलाड़ियों और बस्तर ओलंपिक 2025 में 18 खिलाड़ियों को यूथ आइकन के रूप में चिन्हित किया गया है।

सरगुजा ओलंपिक के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रथम संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इन प्रतियोगिताओं से

प्रतिभावान खिलाड़ियों का चिन्हित किया गया है। सरगुजा ओलंपिक में वर्ष 2026 में 3.49 लाख पंजीयन प्राप्त हुए। सरगुजा ओलंपिक में 12 खेल विधाओं को सम्मिलित किया गया। विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले 14 खिलाड़ियों को यूथ आइकन के रूप में चिन्हित किया गया।

मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स, 2026 के प्रथम संस्करण की मेजबानी छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख शहरों रायपुर, बस्तर एवं सरगुजा में खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स का आयोजन 25 मार्च से 03 अप्रैल 2026 तक सम्यक रूप से आयोजित किए गए। खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स में 7 प्रतिस्पर्धा खेल, 4 डेमो खेल में लाभगमा 3000 प्रतिभागी रहे, इस आयोजन में छत्तीसगढ़ को 3 स्वर्ण, 10 रजत एवं 6 कांस्य समेत कुल 19 पदक प्राप्त हुए।

राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ के पदक विजेला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ण पदक के लिए 2 लाख, रजत पदक के लिए 1.5 लाख एवं कांस्य पदक के लिए 1

लाख की घोषणा की गई है.

अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में खेलों का वातावरण निर्मित करने, खेल अधोसंरचना को विकसित करने, महिला विधाओं को प्रोत्साहित किए जाने, प्रतिभाओं के पहचान के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन प्रावधानित किया गया है, जिसमें 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, फीडर सेंटर, एथलीट वेलफेयर, उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण जैसे विभिन्न पहलुओं पर कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन किए जाने की योजना है।

राज्य खेल अलंकरण समारोह का जिक्र करते हुए बताया कि वर्ष 2024 में पूर्व से लॉबित 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन सरकार द्वारा किया गया, जिसमें 4 वर्षों के कुल 1143 खिलाड़ी खेल अलंकरण पुरस्कार एवं नगद राशि पुरस्कार एवं खेलवृत्ति पाकर लाभान्वित हुए।

छत्तीसगढ़ में यूसीसी की तैयारी, समान नागरिक संहिता पर जनता से मांगे गए सुझाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के बजाय सभी नागरिकों को संविधान के एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से गठित विशेष समिति ने अब आम जनता और विभिन्न संगठनों से उनके सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए हैं। राज्य के नागरिक यह बता सकते हैं कि राज्य में आने वाला नया कानून कैसा होना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा गठित यह 5-सदस्यीय समिति छत्तीसगढ़ में यूसीसी की आवश्यकता और उसकी रूपरेखा का अध्ययन कर रही है। इसके साथ ही समिति व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों व व्यवस्थाओं की भी व्यापक समीक्षा करेगी। समिति ने शासकीय, गैर-शासकीय संगठनों, सामाजिक समूहों, धार्मिक संस्थाओं, समुदायों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे 15 अक्टूबर



2026 तक अपने विचार, राय और अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से जमा करा दें। यूसीसी लागू करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था। उत्तराखंड के अलावा गोवा, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू किया जा चुका है। राज्य में यूसीसी के क्रियान्वयन व सुझावों के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

राज्य के नागरिक और संगठन 15 अक्टूबर तक निम्नलिखित माध्यमों से अपने सुझाव भेज सकते हैं:

ई-मेल: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in

वेब पोर्टल: <https://ucc.cgstate.gov.in/>

डाक द्वारा: कार्यालय समान नागरिक संहिता समिति,न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-201,रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001

एक पेड़ माँ के नाम अभियान से बदली उजड़ी वन भूमि की तस्वीर

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहे ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान ने पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अभियान के तहत अतिक्रमण मुक्त कराई गई वन भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया, जिससे क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और वन संरक्षण को नई दिशा मिली है।जगदलपुर के परियोजना क्षेत्र फरसगांव अंतर्गत बड़े डोंगर पंचायत से लगे वन क्षेत्र में वृहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर बड़ी संख्या में पौधे लगाए।

कार्यालय कार्यापालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क.-1, रायपुर (छ.ग.) निविदा निरस्तीकरण आदेश

इस कार्यालय के निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 08/व.ले.लि. / 2026 27 दिनांक 12.06.2026 सिस्टम निविदा क्र. 193185 द्वारा रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसीवा के जल संसाधन विभाग के शांति नगर कालोनी मिट्टी परीक्षण केन्द्र के पीछे मरीन ड्राइव के पास रिक्त भूमि पर कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर एवं अन्य भवनों का निर्माण कार्य तथा आई. टाईप भवनों का जीर्णोद्धार का कार्य (प्रथम आमंत्रण) राशि रु. 311.85 लाख की निविदा आमंत्रित की गयी थी. संबंधित निविदा में एक ही निविदाकार द्वारा भाग लेने के कारण निविदा निरस्त किया जाता है।

अतः आमंत्रित निविदा सिस्टम क्रमांक 193185 निविदा सूचना क्रमांक 08/व.ले.लि. / 2026-27 दिनांक 12.06.2026 (G-No 262701468 Dated 16.06.2026) को एतद् द्वारा निरस्त की जाती हैं।

सहपत्र शून्य ।

कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र. 1 रायपुर (छ.ग.)
जी-262702520/7

CHHATTISHGARH STATE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (RCR) GUDHIYARI, RAIPUR PH.NO. 0771-2574703 & FAX NO.2593403

No. 10-01/Wk-II/Tender No. 05/1879Raipur, Date 27.07.2026

NOTICE INVITING FOR e-TENDERING

Online bids are invited through CSPCL e-bidding system (SAP SRM) from eligible Contractors for the following works:

Tender No/ Rfx No.	Name of work	Type of Contractor	Total value of tender (in Rs.)	Cost of Tender form (in Rs.)	Date of Submission / Opening
Tender No.05/1879 RFX No. 8100053300	For shifting of overhead 33 KV, 11 KV line X'mer DP & LT line at Jal Grih Marg, Bhatgaon from Datrenga Mod to Chandra Tower Mod Raipur under Changorabhata Zone City Dn. West Raipur.	Class-I/II	30,52,208.00	5000/- (Including GST)	17.08.2026 02.00 / 02.30 PM

Details of Tenders, Technical Specification, Terms & Conditions pre-qualification requirement, online tender fee and EMD submission etc. are available on our website www.cspdel.co.in and ebidding.cspcl.co.in. Tender documents can be downloaded from CSPDCL's official website mentioned above. The cost of required tender fee and EMD should be submitted online up to the date of submission of bid. The tenderer is requested to pay the tender fee and EMD online well before the due date for avoiding complication in network/system. As the tender will not be opened, if the tender fee and EMD payment reference is not shown in system and CSPDCL will not take any responsibility for delay due to network/system so please ensure early submission.

The notice for extension of due date of tender submission, opening /corrigendum/amendment, if any to the tender document will not be published in newspapers. It will only be displayed on CSPDCL's official website as mentioned above and office Notice Board.

SAVE ELECTRICITY

संवाद-48655/3

CHIEF ENGINEER (RCR)
CSPDCL, RAIPUR

तस्लीमा के कार्यक्रम से बदले माहौल के संकेत

बिमल राय

बंगाल में लगभग पांच दशकों तक दो-दो सरकारों के दौर में वोट बैंक की राजनीति का बोलबाला रहा, पर अब यहाँ नई सरकार बनने से हवा काफी बदली हुई लग रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक भी लाश नहीं गिरने से राज्य राजनीतिक हिंसा के कलंक से मुक्त हुआ ही, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने से लोकतंत्र की जुड़ै भी मजबूत होती दिखीं। भाजपा सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार तो हुआ ही, यहां के अल्पसंख्यक समाज में भी संदेश गया है कि अब वे उकसावे में नहीं आने वाले। कोलकाता में तस्लीमा नसरीन के कार्यक्रम में व्यवधान नहीं आना भी एक अच्छा संकेत है। उन्हें ‘काफ़ी दुखी मन से’ कोलकाता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, जिसे वह अपने घर जैसा मानती रही हैं। बांग्ला में तो एक कहावत है, ‘ए पर बांग्ला, ओ पर बांग्ला’। भाषा और संस्कृति में समानता के कारण यह कथन सत्य है। हालांकि, इस वजह से पलायन और घुसपैठ का दंश बंगाल को ही नहीं, पूरे भारत को झेलना पड़ा है। कोलकाता के कार्यक्रम में भी तस्लीमा ने कड़े शब्दों में इस्लामी कट्टरपंथियों की निंदा की। उनका कहना था कि बांग्लादेश में आज कट्टरपंथ पूरी तरह हावी हो चुका है। उन्होंने वहां उन लोगों की हत्याओं की चर्चा की, जो सच बोलने से सुरक्षा मार दिए गए। उन्होंने कहा, ‘जो अपने लिए आधुनिकता चाहते हैं, पर मुस्लिम समाज के लिए मध्ययुगीन व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं, वे मुसलमानों के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो अपनी बेटियों की आजादी को हक कहते हैं और मुस्लिम लड़कियों की गुलामी को उनकी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं, उन्हें प्रगतिशील नहीं माना जा सकता।’ उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी, मुस्लिम समाज में वैज्ञानिक सोच पैदा करने, महिला-पुरुष के समान अधिकारों की चर्चा करते हुए यह भी कहा कि धर्मों के हिसाब से कानून नहीं होना चाहिए। यह कहकर उन्होंने एक तरह से यूसीसी का समर्थन किया, जिसे शुभेंद्रु सरकार लागू करने वाली है। बंगाल में कड़ा गुंडा दमन कानून लाकर सरकार ने हिंसा भड़काने वाले लोगों के मन में भय पैदा किया है। यही वजह है कि पर्व-त्योहारों पर पथराव व आगजनी पर पूरी तरह लगाम लगी है। हाल में, बांकड़ा मस्जिद का मामला लें। नेताजी सुभाष अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के भीतर 160 साल पुरानी मस्जिद हटाने की शुभेंद्रु सरकार की पहल के आगे भी कट्टरपंथी पस्त नजर आ रहे हैं। 11 जुलाई से सुरक्षा और मरम्मत के नाम पर मस्जिद में बाहरी लोगों के प्रवेश और नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। इसके पहले ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी ने वोट बैंक का ख्याल रखते हुए मस्जिद हटाने के संबंध में किए गए प्रयासों को विफल कर दिया था। विरोध में बयानबाजी के बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के बंगाल अध्यक्ष व तृणमूल नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी ने 17 जुलाई को वहां एक करोड़ मुसलमानों को कोला पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए हवाईअड्डे के सात नंबर गेट पर जुटने का आह्वान किया था, पर भारी सुरक्षा इंजांम और धारा 163 लगाने के कारण 10 लोग भी नहीं पहुंचे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के मुताबिक, यह मस्जिद रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर है, जो निरामो (न्यूनतम 240 मीटर की दूरी) का उल्लंघन है। अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद की स्थिति के कारण दूसरे रनवे का पूरा उपयोग हो ही नहीं रहा है, आधुनिक इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएसएस) भी नहीं लग पा रहा है। जहां तक तस्लीमा की बात है, कलम को हथियार बनाकर औरतों पर हो रहे जुल्म, मजहबों कट्टरता व समाज में फैले भेदभाव के खिलाफ तनी रहकर वह अपनी बात साफ-साफ लहजे में कहती रही हैं, जो कट्टरपंथियों के गले नहीं उतरती।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

पचास करोड़ योजन भूमण्डल

पुराणों में उपर्युक्त भूमण्डल का पचास करोड़

योजन परिमाण स्पष्ट करते हुये बतलाया गया है कि-

अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावाभूम्योर्दन्तरम्।

सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यः स्युः पञ्चविंशतिः।।

(देवीभागवत 8।1।4।1।6-17)

अर्थात्- स्वर्ग और भूमि का जो मध्य भाग है वह ब्रह्माण्ड का बीच माना जाता है । इसी केन्द्र स्थान में सूर्य भगवान् विराजते हैं। सूर्यं से सब तरफ पच्चीस करोड़ योजन तक ब्रह्माण्ड की सीमा है ।

तात्पर्य यह हुआ कि सूर्य से पच्चीस करोड़ योजन नीचे और सूर्य से पच्चीस करोड़ योजन ऊपर तक इसी तरह पच्चीस करोड़ योजन बाई तरफ और पच्चीस करोड़ योजन दाई तरफ इतने विस्तृत गोल का नाम ब्रह्माण्ड है । पुराणों में इसी गोले के दो विभाग करके पचास करोड़ योजन को भूगोल के नाम

से और उतने ही परिधाय वाले दूसरे गोलार्ध को खगोल के नाभ याद किया है। इस प्रकार भूमण्डल का पचास करोड़ योजन परिमाण ठीक ही उतरता है।

हमारी पृथ्वी

हम पीछे कह चुके हैं कि पौराणिक वर्णनानुसार विस्तृत भू-मण्डल की जैसी संस्था है, अर्थात् – हमारी पृथ्वी से लेकर सुदूर सूर्ययताप की सीमा पर्य्यन्त सूक्ष्म जगत् में जिन जिन समुद्रों पर्वतों किंवा नदों सरोवर आदिकों का जैसा अस्तित्व विद्यमान है हमारी इस लघुकाय मानव पृथ्वी पर भी उन वस्तुओं के प्रतिनिधि-भूत समुद्र पर्वतादिक ठीक वैसे ही विद्यमान हैं। इसलिये हम पुराणोंक तत्तत्पदार्थों के वर्तमान-कालिक नामों का उल्लेख करते हुये यह बताने की चेष्टा करेंगे कि अब नई पड़ताल के अनुसार भी वर्तमान गवेषकों ने हमारी इस मानव पृथ्वी का जैसा संस्थान निर्धारित किया है।

क्रमशः ...



डॉ. शारदा मेहता

सनातन धर्म में भगवान शंकर का अति महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिमूर्ति के बिना इस सृष्टि की रचना की कल्पना असम्भव है। ये तीनों इस सृष्टि के रचनाकार हैं, रक्षक हैं और संहारक भी है। जब भक्तगण शिव भक्ति साहित्य का अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि शिव के जीवन में श्तीय संख्या का अत्यधिक महत्व है-

1. त्रिनेत्र- इनके तीन नेत्र हैं। इनके तीसरे नेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ज्ञानचक्षु है। यह नेत्र जब शिवजी कुपित होते हैं तब खुलता है। कामदेव पर जब शिवजी क्रोधित हुए तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसको भस्म कर दिया था। यह नेत्र शिव की असीम शक्ति का प्रतीक है। पृथ्वी पर जब अनाचार

अत्याचार और अशान्ति फैलती है तब कुपित शिवजी अपना तृतीय नेत्र खोलकर विश्व में शान्ति स्थापित करते हैं।

2. त्रिशूल- शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। यह भी सत्व, रज और तमो गुण का प्रतीक है। यह तीन कालों का प्रतिनिधित्व करता है। सत, रजत और तमो गुण भी इसमें समाविष्ट है। शिवजी ने गुणों को त्रिशूल रूप में धारण कर रखा है। यह भूत, भविष्य और वर्तमान को इंगित करता है।

3. त्रिपुंड- सफेद चंदन से शिवजी अपने मस्तक पर तीन पंक्तियों से निर्मित तिलक धारण करते हैं जिसे त्रिपुंड कहा जाता है। त्रिपुंड में तीन रेखाएँ होती हैं। प्रत्येक रेखा में नौ देवता होते हैं, इस प्रकार कुल सत्ताईस देवताओं का निवास त्रिपुंड में होता है। त्रिपुंड लगाने से सकारात्मक



ऊर्जा और दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। त्रिपुंड लगाने से अहंकार, अज्ञानता और मोह माया से मुक्ति प्राप्त होती है। त्रिपुंड की तीन रेखाएँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतीक हैं।

4. बिल्व पत्र- भगवान शिव को बिल्व-पत्र अत्यधिक प्रिय है। इसमें भी तीन पत्र होते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती के स्वेद बिन्दु से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसके तीन पत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। बिल्व पत्रों के कुछ वृक्षों पर पाँच और सात पत्रों के बिल्व पत्र भी पाये जाते हैं। भगवान शिव को चढ़ाये जाने के लिए तीन पर्ण वाले अर्खंडित बिल्व पत्र का ही चयन किया जाता है।

5. पुष्प- भगवान शिव को वैसे तो सभी प्रकार के सुगन्धित पुष्प समर्पित किए

ईरान-अमेरिका युद्ध पूरी दुनिया को निगल जाएगा?

डेविड फ्रेंच

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पश्चिम एशिया में संसदीय सहमति के बगैर युद्ध शुरू करने से भी ज्यादा बुरी बात यह है कि अब वह इस युद्ध पर से अपना नियंत्रण खोते जा रहे हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान नीति को लेकर वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से बेहद नाराज हैं, क्योंकि उनके शीर्ष सलाहकार आगे की रणनीति पर किसी साझा निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। युद्ध ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां संघर्ष बढ़ाने से क्षेत्रीय युद्ध के वैश्विक संकट में बदलने का खतरा है, जबकि मौजूदा रणनीति बनाए रखने से अमेरिका के लिए रणनीतिक हार की आशंका बनी हुई है।

दरअसल, ऐसी स्थिति की आशंका शुरुआत से ही थी। ट्रंप ने ऐसे देश से टकराव मोल लिया, जिसकी सैन्य और क्षेत्रीय क्षमता सद्दाम हुसैन के 2003 वाले इराक से कहीं अधिक मजबूत है, पर उसके अनुरूप सैन्य तैयारी नहीं की। ट्रंप को विश्वास था कि सीमित हवाई हमलों, अधिक दबाव व जनविद्रोह के सहारे वह एक क़रूर तानाशाह सरकार को गिरा देंगे। उन्होंने कई बार संकेत दिया कि ईरान में भी वेनेजुएला जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन, यह आकलन गलत साबित हुआ। जब शुरुआती रणनीति विफल हो गई, तब ट्रंप प्रशासन के पास कोई ठोस 'प्लान बी' नहीं था, सिवाय इसके कि ईरान पर और बम गिराए जाएं और उससे घुटने टेकने की उम्मीद की जाए। ट्रंप के सार्वजनिक बयान भी इस रणनीतिक असमंजस को उजागर करते हैं। एक दिन उन्होंने नए हवाई हमलों का आदेश देते हुए कहा कि ईरान झुक जाएगा, और अगले ही दिन उन्होंने दूरस्थ सोशल पर दावा किया कि ईरान और अन्य क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर उन्होंने हमले रोकने का फैसला किया है। इन विरोधाभासी बयानों से साफ है कि वाशिंगटन के पास कोई स्थिर रणनीति नहीं है। दरअसल, असल चुनौती केवल युद्ध जीतने की नहीं, उस पर नियंत्रण बनाए रखने की है। लंबे समय तक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति रहने के



कारण अमेरिका इस सोच का आदी हो चुका है कि वह जब चाहे युद्ध शुरू कर सकता है और जब चाहे खत्म भी। पर, ईरान के साथ संघर्ष ने इस धारणा को चुनौती दी है। अगर बात इराक व अफगानिस्तान के युद्ध की करें, तो वे विनाशकारी ज़रूर थे, लेकिन उनका दायरा सीमित था। उनमें न तो विरोधियों के पास अमेरिकी ठिकानों को व्यापक नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी और न ही युद्ध में दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियां सीधे तौर पर शामिल थीं। अब तस्वीर बदल चुकी है। दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, जहां विश्वयुद्ध की आशंका बढ़ रही है। चिंताजनक बात यह है कि हालात पर किसी का भी पूरा नियंत्रण नहीं दिखता, अमेरिकी राष्ट्रपति का भी नहीं।

ईरान न केवल अमेरिकी ठिकानों पर प्रभावी हमले कर रहा है, बल्कि उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को भी लगातार निशाना बनाया है। तेल और गैस से जुड़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा संरचनाओं पर हमले तथा होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खराब बन चुका है। इसी बीच हूती विद्रोहियों की सक्रियता ने संघर्ष

को लाल सागर तक फैला दिया है। खबर है कि सऊदी अरब अब हूती-नियंत्रित इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं, यूक्रेन द्वारा कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हमला, रूस और चीन की संभावित सैन्य व खुफिया सहायता तथा रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन द्वारा ईरान को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति को खबरें इस संघर्ष को व्यापक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदलती दिखाई देती हैं।

यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिका दो कड़वी सैन्य सच्चाइयों का सामना कर रहा है। पहली, ईरान ने यह दिखा दिया है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने पहले जितने अभेद्य नहीं रहे। इराक युद्ध के दौरान अल-कायदा के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं थीं और सद्दाम हुसैन भी क्षेत्र में इतने प्रभावी हमले नहीं कर सके थे, जितने ईरान ने उस संघर्ष में किए हैं। बेशक, ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके कई वरिष्ठ सैन्य व राजनीतिक नेता मारे गए हैं। पर, अमेरिका और ईरान को युद्ध को लेकर मानसिकता अलग-अलग है। वाशिंगटन अपने सैनिकों व हथियारों के नुकसान को अत्यंत गंभीर मानता है, जबकि ईरानी शासन सत्ता और रणनीतिक उद्देश्यों की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि केवल शीर्ष नेतृत्व को समाप्त कर देने से निर्णायक जीत की उम्मीद अब तक पूरी नहीं हुई है। दूसरी, अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य



प्रशांत किशोर ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उनके सामने एक स्थिर चेहरा था, एक स्थिर संदेश था और चुनाव को लेकर पहले से तैयार राजनीतिक कथा थी। दूसरी ओर भाजपा को नए उम्मीदवार के साथ संगठन और मतदाता के बीच नया तालमेल बनाना पड़ा।

बांकीपुर में भाजपा के लिए एक और चुनौती यह थी कि इस बार चुनाव उसके पुराने विधायक के व्यक्तिगत प्रभाव के बिना हो रहा था। किसी भी मजबूत विधानसभा क्षेत्र में पार्टी नहीं उम्मीदवार की ताकत हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई बार विधायक की व्यक्तिगत लोकप्रियता पार्टी के वोट को अतिरिक्त मजबूती देती है। जब वही चेहरा मैदान में नहीं होता तो पार्टी को यह साबित करना पड़ता है कि उसका संगठन और वोट बैंक अपने दम पर भी उतना ही मजबूत है। पीके ने इसी अंतर को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने चुनाव को व्यक्ति बनाम व्यक्ति की लड़ाई में बदल दिया। भाजपा का संगठन उनके सामने था, लेकिन दूसरी तरफ पीके खुद एक राजनीतिक ब्रांड के रूप में मैदान में थे। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वोटों का बंटवारा रहा। भाजपा के सामने प्रशांत किशोर के साथ अन्य राजनीतिक ताकतें भी थीं। ऐसी स्थिति में किसी उम्मीदवार को जीत केवल उसके वोट बढ़ने से नहीं होती, बल्कि यह भी तय करता है कि बाकी उम्मीदवारों के वोट कितने हिस्सों में बंटेंगे।

पीके की रणनीति यह थी कि वह खुद को मुख्य मुकाबले का चेहरा बना दें। जब किसी तीसरे उम्मीदवार को मतदाता मुख्य मुकाबले में पहुंचा हुआ मानने लगता है तो उसके पक्ष में मतदान करने की मनोवैज्ञानिक बाधा कम हो जाती है। संभवतः बांकीपुर में यही बदलाव देखने को मिला। पीके ने अपने पक्ष में केवल जन सुराज समर्थकों को नहीं जुटाया, बल्कि दूसरे दलों से असंतुष्ट और बदलाव चाहने वाले

मतदाताओं के बीच भी जगह बनाई।

राजद की मौजूदगी ने भी चुनाव को बहुकोणीय बनाया। भाजपा के लिए यह स्थिति पूरी तरह नुकसानदेह नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सामान्य तौर पर बहुकोणीय मुकाबला उसके लिए फायदे का हो सकता है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने उस तीसरे राजनीतिक स्पेस पर कब्जा कर लिया, जिसे भाजपा और राजद के बीच असंतुष्ट मतदाताओं के लिए खुला माना जा सकता था। यही पीके की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने चुनाव को केवल भाजपा विरोधी वोट की लड़ाई नहीं बनाया, बल्कि इसे नए विकल्प के चुनाव में बदल दिया। यह अंतर छोटा दिखाई देता है, लेकिन चुनावी राजनीति में यही अंतर परिणाम बदल देता है। भाजपा की एक बड़ी कमजोरी शायद यह रही कि उसने बांकीपुर को केवल एक सामान्य चुनावी सीट की तरह नहीं, बल्कि अपने मजबूत गढ़ के रूप में देखा। मजबूत सीटों पर दलों में आत्मविश्वास स्वाभाविक है, लेकिन यही आत्मविश्वास कभी-कभी अतिरिक्त सावधानी को कम कर देता है।

पीके ने इस मानसिकता को चुनौती दी। उनका पूरा अभियान इस संदेश पर आधारित था कि कोई भी सीट स्थायी रूप से किसी दल की नहीं होती। मतदाता अगर बदलाव चाहता है तो वह मजबूत से मजबूत राजनीतिक किले को भी हिला सकता है।

भाजपा के पास संगठन था, कार्यकर्ता थे और राजनीतिक अनुभव था। पीके के पास एक चुनावी कहानी थी। यही दोनों के अभियान का सबसे बड़ा अंतर रहा। भाजपा का संदेश मुख्यतः पार्टी, सरकार और संगठन की ताकत के इर्द-गिर्द रहा, जबकि पीके ने अपने अभियान को व्यक्ति और बदलाव की कहानी में बदला। उन्होंने मतदाता को यह महसूस कराने की कोशिश की कि वह केवल एक उम्मीदवार को नहीं, बल्कि राजनीति के एक नए प्रयोग को वोट दे रहा है। चुनावों में संगठन ज़रूरी है, लेकिन संगठन को मतदाता को भावनाओं और अपेक्षाओं से जोड़ने वाली कहानी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। बांकीपुर में पीके इस मोर्चे पर भाजपा से आगे निकलते दिखाई दिए।

भाजपा की चूक को केवल उम्मीदवार चयन तक सीमित करना सही नहीं होगा। असली चूक कई स्तरों पर दिखाई देती है। पार्टी शायद यह पूरी तरह नहीं समझ सकी कि उसके सामने कोई सामान्य निर्दलीय या नई पार्टी का उम्मीदवार

नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का माहिर व्यक्ति मैदान में है। पीके ने भाजपा के पारंपरिक चुनावी ढांचे का अध्ययन किया हुआ है और उन्हें पता है कि मजबूत संगठन की कमजोर नस कहाँ हो सकती है। दूसरी चूक यह रही कि भाजपा पीके को लंबे समय तक एक सीमित चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक संदेश वाले उम्मीदवार के रूप में शायद उतनी आकामकता से नहीं रोक सकी। परिणामस्वरूप पीके का नाम ही चुनाव की मुख्य कहानी बनता गया।

तीसरी चूक मतदाताओं के उस हिस्से को लेकर रही, जो भाजपा के पारंपरिक समर्थक तो नहीं थे, लेकिन राजद के साथ भी जाना नहीं चाहते थे। यही वर्ग पीके के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जमीन बना। बांकीपुर का परिणाम बिहार की राजनीति में शहरी मतदाता के बदलते व्यवहार पर भी चर्चा को मजबूर करेगा। शहरों में मतदाता के मुद्दे हमेशा जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रहते। रोजगार, शिक्षा, प्रशासन, बुनियादी सुविधाएँ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक जवाबदेही और बेहतर प्रतिनिधित्व जैसे सवाल भी प्रभाव डालते हैं। पीके ने इसी वर्ग के बीच अपनी राजनीतिक जगह बनाने का प्रयास किया। अगर यह प्रयोग सफल रहा है तो इसका अर्थ यह होगा कि बिहार के शहरी मतदाता के बीच तीसरे विकल्प की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है।

हालांकि बांकीपुर की जीत प्रशांत किशोर के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। एक शहरी विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करना और पूरे बिहार में राजनीतिक संगठन खड़ा करना दो अलग बातें हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, पंचायत स्तर का संगठन और सामाजिक गठजोड़ कहीं ज्यादा निर्णायक होते हैं। पीके को अब यह साबित करना होगा कि उनकी राजनीति केवल उनके व्यक्तिगत चेहरे तक सीमित नहीं है और जन सुराज अलग-अलग सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्रों में भी मजबूत संगठन खड़ा कर सकता है।

भाजपा के लिए बांकीपुर का परिणाम एक चेतावनी है। सवाल यह नहीं है कि एक सीट चली गई। सवाल यह है कि क्या उसके मजबूत शहरी आधार में नए राजनीतिक विकल्प के लिए जगह बनने लगी है। अगर यह सिर्फ एक उपचुनाव का स्थानीय परिणाम है तो भाजपा के लिए चिंता सीमित है।

आज का इतिहास

- 1945 अमेरिकी हवाई जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था।
- 1949 इंडाडोर की राजधानी क्रिदो में आये 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप से छह हजार लोगों की मौत हुई।
- 1949 अंबादो, इक्वाडोर के पास 6.8 एमएल के भूकंप में 5,050 लोग मारे गए।
- 1962 अभिनेत्री और मॉडल मर्लिन मुनरो को लॉस एंजिल्स के अपने घर इन बर्थवुड में मृत पाया गया, एक ऐसी घटना जो सबसे अधिक विवादास्पद साजिश सिद्धांतों में से एक का केंद्र बन गई है।
- 1963 एक आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस थे। प्रतिबंध वातावरण, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के भीतर परीक्षण को समाप्त करता है।
- 1966 कैसर्स प्लेसस होटल और कैसीनो लास वेगास में खुला।
- 1995 ऑपरेशन स्टॉर्म के दौरान, कोएशियाई बलों ने रिपब्लिक ऑफ सर्बियाई ऋजिना से केनिन शहर को बरामद किया।
- 2003 एक आत्मघाती हमलावर ने इंडोनेशिया के दक्षिण जकार्ता के सेतिवुडी में जेजेडब्ल्यू मैरियट होटल की लांबी के बाहर एक कार बम विस्फोट किया, जिसमें बारह लोगों की मौत हो गई और 150 घायल हो गए।
- 2005 पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने औपचारिक रूप से हांगकांग के रिपोर्टर चिंग चेंगोंग पर जासूसी करने का आरोप लगाया। वह द स्ट्रेट्स टाइम्स के लिए एक पत्रकार हैं।
- 2006 चूँकि मानव अधिकार संगठन आंतरिक मंत्रालय द्वारा अधिकृत नहीं था, इसलिए ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार के लेखक शिरीन एबादी पर प्रतिबंध लगा दिया।
- 2007 मोज़ाम्बिक के अधिकारियों ने नकली दृथपेस्ट के हजारों बक्से पर कब्जा कर लिया है, जो मानते हैं कि उनके पास खतरनाक रासायनिक डि-इथाइलीन ग्लाइकोल हो सकता है।
- 2010 युद्ध में अफगानिस्तान-दस विदेशी सहायता श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिशन के कार्यकर्ताओं को बड़खल प्रांत के कुरानामा मुंजुन जिले में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मार दिया गया।
- 2011 केफ केनवरल एयर फोर्स स्टेशन से बृहस्पति के लिए जाने वाले पहले सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान जूनो को प्रक्षेपण किया गया।
- 2012 विस्कॉन्सिन के ओक क्रेक में एक सिख मंदिर पर हमला करने के बाद सात लोगों की मौत हो गई। हालाँकि, शूटर को पुलिस ने गोलीबारी में मार दिया था।

तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद आखिर जाएंगे कहां?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसद खुद को एनसीपीआई के साथ बता रहे हैं और एनडीए की बैठकों में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा के रिकॉर्ड में अभी उनकी पहचान टीएमसी सांसद की है। एनसीपीआई को संसदीय मान्यता नहीं मिलने से सवाल उठ रहा है कि आखिर इन सांसदों की वास्तविक राजनीतिक और संसदीय पहचान क्या है? राजनीति में कई बार किसी फैसले से ज्यादा महत्वपूर्ण वह सवाल होता है, जो उस फैसले के बाद खड़ा होता है। टीएमसी के 20 सांसदों के अलग होने के मामले में भी यही हो रहा है। एक तरफ वे एनसीपीआई के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ संसद के रिकॉर्ड में अभी भी टीएमसी के सदस्य हैं।

अब चर्चा केवल यह नहीं कि ये सांसद टीएमसी से अलग क्यों हुए। असली सवाल यह है कि वे जाएंगे कहाँ? एनसीपीआई में रहेंगे, भाजपा का दामन थामेंगे या इन्हें से कुछ फिर ममता बनर्जी के साथ लौटेंगे?

20 सांसद खुद को एनसीपीआई के साथ बता रहे हैं और एनडीए की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन लोकसभा के रिकॉर्ड में उनके नाम के साथ अभी भी एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दर्ज है।

एनसीपीआई को लोकसभा अध्यक्ष की ओर से औपचारिक मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में राजनीतिक पहचान और संसदीय पहचान के बीच अंतर दिखाई दे रहा है।

सवाल है कि क्या यह केवल प्रक्रिया का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बन रहा है?

टीएमसी के वरिष्ठ सांसद और अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने संकेत दिया है कि अगले एक सप्ताह में बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। इससे यह संभावना मजबूत हुई है कि टीएमसी इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकती है। कल्याण बनर्जी का कहना है कि टीएमसी छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल के साथ जाने वाले सांसदों पर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी कानून लागू होना चाहिए। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो विवाद सिर्फ 20 सांसदों की सदस्यता तक सीमित नहीं रहेगा।

सवाल यह भी होगा कि राजनीतिक दल छोड़ने, नया समूह बनाने और संसदीय मान्यता मिलने के बीच दसवीं अनुसूची किस तरह लागू होगी।

इस कहानी का सबसे दिलचस्प राजनीतिक पहलू एनसीपीआई का भविष्य है। एनसीपीआई को मान्यता मिलने में देरी के



बीच यह चर्चा है कि बागी सांसद आगे चलकर भाजपा में विलय कर सकते हैं। इसकी अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए इसे राजनीतिक अटकल से ज्यादा नहीं माना जा सकता।

सवाल लेकिन जरूर बढ़ा है, अगर मंजिल भाजपा है तो एनसीपीआई का रास्ता क्यों चुना गया? क्या एनसीपीआई एक स्थायी राजनीतिक विकल्प है या किसी बड़े राजनीतिक पुनर्संयोजन से पहले का अस्थायी पड़ाव?

इधर एनसीपीआई के तीन सांसदों- अबू ताहेर खान, खलीलुर्रहमान और यूसुफ पठान के टीएमसी में लौटने की खबरें भी हैं। यदि तीनों की वापसी होती है तो टीएमसी की

संख्या आठ से बढ़कर 11 और एनसीपीआई की संख्या 20 से घटकर 17 हो जाएगी। यानी एनसीपीआई दो-तिहाई के आंकड़े से नीचे चली जाएगी।

संख्या का केवल बदलाव नहीं होगा। इससे पूरे दल-बदल विवाद का राजनीतिक और संवैधानिक गणित बदल सकता है।

बागी सांसदों की कहानी के बीच टीएमसी के कुछ नेताओं की भाजपा नेताओं से मुलाकातों ने भी राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है। कल्याण बनर्जी को भाजपा सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य के साथ देखा गया। उनके साथ महुआ मोइत्रा भी थीं। सोनात राय और शत्रुघ्न सिन्हा को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ भोजन की मेज पर देखा गया। शताब्दी राय की प्रधानमंत्री मोदी से और जून मालिया की गुहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं।

इन मुलाकातों को पाला बदलने का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। लोकतंत्र में अलग-अलग दलों के नेताओं का मिलना असामान्य नहीं है। लेकिन जब एक पार्टी टूट के दौर में हो, तब राजनीतिक तस्वीरों का महत्व भी बढ़ जाता है।

यहीं से सवाल 20 सांसदों से आगे निकल

जाता है। क्या भाजपा केवल टीएमसी के असंतुष्ट सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है? या बंगाल में इससे बड़ा राजनीतिक पुनर्संयोजन तैयार हो रहा है? अभी इसका जवाब नहीं है। लेकिन घटनाक्रम को देखते हुए इन सवालों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता।

पूरे मामले में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। एनसीपीआई को संसदीय मान्यता मिलेगी या नहीं और बागी सांसदों की संसदीय पहचान क्या होगी- इन सवालों पर संसदीय प्रक्रिया निर्णायक होगी। लेकिन प्रक्रिया में देरी के साथ राजनीतिक असमंजस भी बढ़ता जा रहा है।एक तरफ जमीन पर सांसद एनसीपीआई और एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ संसद के रिकॉर्ड में वे अभी भी टीएमसी सांसद हैं।यही अंतर इस पूरे मामले को असाधारण बनाता है। टीएमसी अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उसे केवल सांसदों के पार्टी छोड़ने का तथ्य नहीं रखना होगा। उसे यह भी स्पष्ट करना होगा कि इस स्थिति में संविधान की दसवीं अनुसूची कैसे लागू होती है।दूसरी ओर बागी सांसदों के सामने भी अपनी राजनीतिक पहचान स्पष्ट करने की चुनौती होगी।क्या वे एनसीपीआई में रहेंगे? क्या भाजपा के साथ जाएंगे? या कुछ

सांसद वापस टीएमसी में लौटेंगे? अभी तीनों संभावनाएं राजनीतिक चर्चा का हिस्सा हैं।

बंगाल की राजनीति में दल बदल और राजनीतिक पाला बदल कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार मामला इसलिए अलग है क्योंकि राजनीतिक निष्ठा, संसदीय पहचान और संवैधानिक प्रक्रिया तीन अलग-अलग दिशाओं में जाती दिख रही हैं।अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन 20 सांसदों का अंतिम ठिकाना क्या होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है- एनसीपीआई की संसदीय मान्यता पर फैसला जितना लंबा खिंचेगा, राजनीतिक अटकलें उतनी ही तेज होंगी। आखिर सवाल सिर्फ यह नहीं है कि तृणमूल के बागी सांसद किस दल में?

सवाल यह है कि वे संसद में किस पहचान के साथ हैं और आने वाले समय में जनता के सामने किस राजनीतिक पहचान के साथ खड़े होंगे? अगर अगले एक सप्ताह में कल्याण बनर्जी के संकेत के मुताबिक कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, तो बंगाल की राजनीति में नई तस्वीर बन सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता, तो भी मौजूदा असमंजस एक सवाल जरूर छोड़ जाएगा- दल बदलना शायद आसान है, लेकिन अपनी राजनीतिक पहचान तय करना सबसे मुश्किल।

पाक आंतरिक संकट से घिरने पर करता है कायराना कृत्य

ज्योति भास्कर

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की नाम पूछकर की गई हत्या सिर्फ एक और आतंकी वारदात नहीं, बल्कि देश के सामाजिक सद्भाव और जम्मू-कश्मीर में सामान्य होते जन-जीवन पर एक सुनियोजित हमला है।

पिछले वर्ष अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की पहचान पूछकर हत्या कर दी गई थी, की तरह ताजा हमले की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा के मुखौटा समूह द रेंजस्ट्रेस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली है। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तानी आतंकी समूहों के इरादे वही पुराने हैं- कश्मीर में भय का वातावरण बनाना, विकास की प्रक्रिया को बाधित करना और देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच अविश्वास पैदा करना।

पिछले छह वर्षों में टारगेट किलिंग की ऐसी वारदातों में जिन हियालीस लोगों की जाने गई हैं, उससे आतंकियों की मंशा का पता चलता है। वे जानते हैं कि निर्दोष लोगों की हत्या से भय का प्रभाव अधिक व्यापक होता है और उसकी अंतरराष्ट्रीय चर्चा भी होती है। आतंकियों की रणनीति भी यही होती है कि कम संसाधनों में अधिकतम दहशत पैदा की जाए। इन सभी घटनाओं को पाकिस्तान की व्यापक रणनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और सीमा पार आतंकी ढांचे पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के अलावा भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अपनाई गई कठोर नीति के बीच पाकिस्तान लगातार ऐसे प्रॉक्सि संगठनों का सहारा लेता रहा है, जो उसकी बढ़ती हताशा को दर्शाता है। टीआरएफ जैसे नामों का उपयोग ही पाकिस्तानी आतंकी फैक्टरी ने



इसलिए किया, ताकि आतंकवाद को स्थानीय असंतोष का रूप देकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित किया जा सके। जबकि, हकीकत यह है कि इन संगठनों के प्रशिक्षण, हथियार, पैसा और वैचारिक समर्थन की डोर आज भी सीमा पार से ही संचालित होती है।

यह भी गौरतलब है कि जब-जब पाकिस्तान आंतरिक संकटों से घिरता है या पीओके से जुड़े प्रश्न अंतरराष्ट्रीय चर्चा में आने लगते हैं, तब-तब सीमा पार से आतंकी गतिविधियों में भी तेजी देखी जाती है। दरअसल, आतंकवाद पाकिस्तान के लिए सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक व कूटनीतिक उपकरण रहा है।

ऐसे में इन आतंकी हमलों पर प्रतिक्रिया देने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस पूरी संरचना को कमजोर किया जाए, जिसके बल पर आतंकी संगठन सक्रिय बने रहते हैं। इसके लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पाकिस्तान का असल चेहरा सामने लाने की कोशिशें करते रहना होगा। इसके अतिरिक्त, भारत को अपने सुरक्षा तंत्र को और अधिक सक्षम बनाना होगा, वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर में विकास, लोकतंत्र और सामाजिक समरसता की प्रक्रिया को बिना रुके आगे बढ़ाते रहना होगा और यही आतंकवाद का सबसे प्रभावी उत्तर भी होगा।

एनडीए सांसदों के सत्रीय मंगल मिलन के सियासी मायने

कमलेश पांडे

केंद्र में पिछले 12 वर्षों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार इन दिनों पुनः उस एकजुट विपक्ष के निशाने पर है, जिसे वह अबतक चुनावी सियासी पाट पर पछाड़ते आई है। लेकिन जिस तरह से बहुरूपिया विपक्ष कभी मुसलमानों के छव्य वेश में, कभी किसानों के रूप में और कभी छात्रों के छव्य वेश में जिस तरह से मोदी सरकार को घेरने पर तुला हुआ है, उसके पीछे विदेशी हाथ से इंकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी सरकार सबसे जूझ रही है!

हाल ही में छात्र आंदोलन की कथित सफलता से घबराई सरकार ने जिस तरह से अपने ओबीसी रणनीतिका शिक्षा मंत्री की राजनीतिक बलि चढ़ाई है, और इससे उत्साहित कांक्रोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने जिस घमंड का प्रदर्शन किया, उससे विपक्ष उत्साहित है। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुहमंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लिया जाने लगा है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का अतीत और खुद देश का भविष्य करार दिया है, उसके मुताल्लिक इतना ही इशारा करना काफी होगा कि भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने देश का भविष्य तय कर दिया है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आगे करके एक तीर से कई शिकार करने की योजना बनाई है, क्योंकि भाजपा की ओबीसी राजनीति में श्री चौधरी अपने नैसर्गिक सियासी गुणों के चलते फिट बैठते हैं। ये अभी अंदरखाने की बात है, लेकिन राहुल गांधी को आगाह करने के लिए मैंने इस सच्चाई को



डिस्कलोज कर दिया है, जो हिंदी पट्टी के मिजाज पर फिट बैठता है।

शायद यही वजह है कि भाजपा नेतृत्व ने अपने सर्वाधिक संकटग्रस्त काल से गुजरते हुए अपने सांसदों और सहयोगी सांसदों को याद किया, जिसे राजनीतिक गलियारे में एनडीए सांसदों के मंगल मिलन की उपमा दी गई है। हालांकि यह अनौपचारिक बैठक, संवाद या सामूहिक कार्यक्रम संसद सत्र के दौरान हरेक मंगलवार को आहूत होती है। हालिया एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक गत 28 जुलाई 2026 (मंगलवार) को, संसद के मानसून सत्र के दौरान हुई।

यह मंगल मिलन नाम से आयोजित होने वाली नियमित मंगलवार की संसदीय दल की बैठक थी। जो नई दिल्ली में संसद पुस्तकालय भवन (Parliament Library Building) के जीएनसी बालयोगी ऑडिटोरियम (GMC Balayogi Auditorium) में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, संसदीय कार्य मंत्री तथा एनडीए के अनेक सांसद और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

इसमें एनडीए के सभी प्रमुख घटक

दलों के सांसद शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल (यूनाइटेड), तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) [LJP(RV)], हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM), अपना दल (सोनेलाल) अन्य एनडीए सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। खास बात यह कि पहली बार नेशनलिस्ट सिटीजनस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सांसद भी बैठक में शामिल हुए, क्योंकि पार्टी को हाल में एनडीए का सहयोगी बनाया गया है। इस बैठक की सबसे चर्चित बात NCPI सांसदों की पहली भागीदारी रही, जिसे एनडीए के विस्तार और संसद में संख्या एवं राजनीतिक समन्वय को मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा गया।

इस मंगल मिलन के कई राजनीतिक और संगठनात्मक संकेत/मायने निकलकर सामने आते हैं-

पहला, संगठनात्मक एकजुटता का प्रदर्शन: यह विपक्ष और सहयोगी दलों को संदेश कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं।

दूसरा, संसद सत्र की रणनीति: संसद में सरकार के विधेयकों, विपक्ष की रणनीति

और विभिन्न मुद्दों पर साझा रख तय करने का अवसर समझा जाता है।

तीसरा, आगामी चुनावों की तैयारी: देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले सांसदों को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने और जनता से संवाद बढ़ाने का संदेश दिया गया।

चौथा, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार: सांसदों को निर्देश दिया जा सकता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाएं।

पांचवां, सहयोगी दलों को महत्व: एनडीए में शामिल छोटे और क्षेत्रीय दलों को सम्मान और भागीदारी का संदेश देकर गठबंधन को मजबूत बनाए रखना है।

छठा, विपक्षी इंडिया गठबंधन को राजनीतिक संदेश: यह दिखावा कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई असमंजस नहीं है और गठबंधन स्थिर है।

सातवां, 2029 की दीर्घकालिक रणनीति: केवल वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों पर नहीं, बल्कि अगले लोकसभा चुनाव तक संगठन और जनसंपर्क को मजबूत करने की दिशा में तैयारी।

उल्लेखनीय है किभारतीय राजनीति में ऐसे कार्यक्रम अक्सर केवल सामाजिक मेल-मिलाप नहीं होते, बल्कि इनके माध्यम से राजनीतिक संदेश दिए जाते हैं, सांसदों का मनोबल बढ़ाया जाता है, संगठनात्मक अनुशासन मजबूत किया जाता है, और भविष्य की रणनीति पर औपचारिक चर्चा होती है। इसलिए मंगल मिलन को केवल सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के बजाय राजनीतिक समन्वय, गठबंधन प्रबंधन और चुनावी तैयारी के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी देखा जा सकता है।

नंदन नीलेकणी से ‘लीक-प्रुफ’ परीक्षा सुधार की उम्मीद!

डा. वरिंदर भाटिया

प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के लिए तारीफ की जा सकती है कि जब भी देश हित को लेकर किसी समस्या को हल करना होता है, तो पाटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनके द्वारा काबिल और विद्वान लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। उदाहरण के लिए, पाक के साथ युद्ध के बीच देश का पक्ष विदेशों में रखने के लिए भेजे गए शशि थरूर, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी इत्यादि कई नाम लिए जा सकते हैं। यह ठीक उसी तरह है, जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमृतसर से कई बार सांसद पूर्व विदेश राज्य मंत्री, बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल दिवंगत रघुनंदन लाल भाटिया को चीन से जुड़े मामलों को लेकर जिम्मेदारी दी थी।

और अब प्रधानमंत्री मोदी ने देश में परीक्षा सुधारों को लेकर ‘आधार’ के जनक नंदन नीलेकणी को परीक्षा सुधार दल समिति का जिम्मा सौंपा है। एक बात तो विश्वसनीय लगती है कि नैशनल टैस्टिंग एजेंसी (एन.टी.ए.) के तहत होने वाले बड़े-बड़े एग्जाम्स जैसे नीट और सी.यू.ई.टी. के तपाड़े कलह-क्लेश के बाद उच्चस्तरीय पैनल/समिति में नीलेकणी जैसे धुरंधरों को जोड़ने से लीक-फ्रूफ टैक-सिस्टम की उम्मीद की जा सकती है।

नंदन नीलेकणी वही विद्वान हैं, जिन्होंने ‘आधार’ का पूरा ढांचा बनाकर 1.4 अरब से अधिक लोगों का बायोमैट्रिक डाटा एक जगह सेंट कर दिया और यू.पी.आई. की नींव रखकर गली-नुकड़ पर चाय बेचने वाले से लेकर बड़े शोरूम तक का कैशलेस सीन ऑन कर दिया। अब जब यह विद्वान एग्जाम रिफॉर्मस के मैदान में उतारा गया है, तो पहला बड़ा बदलाव हो सकता है ‘एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन’ और ‘ऑटोमेटेड क्रेक़न पेपर



जनरेशन’ का। मतलब, अब वे दिन गए जब पचां छपने प्रैस में जाता था और रास्ते में ही कोई शातिर एजेंट लीक करवा कर छा जाता था। अब पेपर सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोग्राफी से एग्जाम टाइम से कुछ मिन्ट पहले ही सेंटर पर डिजिटल अनलॉक होगा, जिससे किसी के भी घुर्चा चुराने के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे।

दूसरा बड़ा रिफॉर्म है ‘बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन’ और ‘सैंट्रलाइज्ड सर्वर सिक्वोरिटी’। नीलेकणी का ट्रैक रिकॉर्ड गवाही देता है कि वह डुप्लीकेसी और ‘मुन्नाभाई’ टाइप के फर्जीवाड़े का खेल एक झटके में खत्म कर देते हैं। पहले क्या होता था कि सोना की जगह मोना जाकर पेपर में बैठ जाती थी, फोटो मैच नहीं होती थी और सेंट्रिंग से बायोमैट्रिक बाइपास हो जाता था। लेकिन नीलेकणी स्ट्राइड में अब आधार आधारित 2-फैक्टर बायोमैट्रिक (आईरिस और फिंगरप्रिंट) और ए.आई.-संचालित फेस-रिकग्निशन तकनीक सीधे एग्जाम हॉल के गेट पर लग सकती है।

जैसे ही कोई फर्जी बंदा हॉल में घुसेगा, सिस्टम तुरंत लाल बत्ती जला देगा और पुलिस की गाड़ी बाहर ही खड़ी मिलेगी। एग्जाम सेंट्रों में जो सी.सी.टी.वी. फुटेज और ओ.एम.आर. सीट की चैकिंग का ढीला-ढाला

काम महीनों तक लटकता था, उसे नीलेकणी का ‘ओपन डाटा डिजिटल आर्किटेक्चर’ (जैसे यू.पी.आई. और एकाऊंट एप्रोग्रेट सिस्टम) कुछ ही दिनों में पूरा कर देगा। यानी सारा काम 100 प्रतिशत ट्रांसपैरेंट होगा, जिसमें किसी दलाल या बाबू को हाथ मारने की रती भर भी जगह नहीं मिलेगी।

‘एड्रैप्टिव टैस्टिंग’ और ‘लो-बैंडविड्थ क्लाइड इंफ्रास्ट्रक्चर’ दूर-दराज के गांवों और छोटे शहरों के छात्रों की मुश्किलों को आसान कर देगा। अक्सर क्या होता है कि कम्प्यूटर बेस्ड टैस्ट (सी.बी.टी.) में गांव-देहात के सेंट्रों पर सर्वर डाउन हो जाता है या स्क्रीन हैंग हो जाती है और गरीब बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाता है।

नीलेकणी की पूर्व कार्य शैली को देखें तो उनका पूरा फोकस हमेशा ‘स्कैलेबिलिटी’ पर रहता है, यानी ऐसा सिस्टम बनाओ, जो करोड़ों यूजर्स का लोड एक साथ बिना क्रैश हुए झेल सके। यह बिल्कुल डिजिटल इंडिया और यू.पी.आई. की तरह है, जो हर सैंकड़ लाखों ट्रांज़ेक्शन बिना अटके निपटाता है। तो उम्मीद यह है कि वह एक ऐसा ‘डिस्ट्रिब्यूटेड टैस्टिंग नैटवर्क’ खड़ा करेंगे, जहां इंटरनेट चले न चले, लोकल सर्वर पर छात्र बिना किसी रुकावट के टैस्ट दे सकेगा और और डाटा अपने आप सिंक हो जाएगा।

साथ ही, बार-बार पेपर लीक की वजह से लाखों छात्रों की पूर्व भरोसा हिला है, उसे वापस लाने के लिए वह एक ‘डिजिटल ट्रिगर एंड ऑडिट ट्रेल’ लागू करेंगे, जिससे पेपर का एक-एक क्लिक और एक्सेस लॉग ट्रैक होगा, कि किस टाइम पर किसी बंदे ने डाटा को छुड़ा। कुल मिलाकर नीलेकणी के आने से एग्जाम सिस्टम का काफी ‘कचरा’ साफ होने की उम्मीदें हैं ताकि हमारे छात्रों को उनका हक मिलता रहे।

डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल और हमास के बीच समझौते का ऐलान

सनत जैन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बड़ा दावा किया है। इस दावे में उन्होंने कहा है, इजराइल और हमास के बीच में जल्द ही समझौता होने जा रहा है। हमास और उसके दूसरे सभी हथियारबंद संगठन अपने हथियार छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। इजराइल भी गाज़ा से हटाने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा, कि गाजा का कंट्रोल अब फिलिस्तीन सरकार के हाथ में आएगा। दोनों लोग मिलकर बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेंगे। इस समझौते के बाद इजराइल और गाजा के बीच में स्थाई शांति स्थापित होगी। एक-दूसरे के ऊपर कोई हमले नहीं होंगे। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि यह समझौता कई चरणों में लागू होगा। जैसे ही हमास अपने हथियार छोड़गा इजराइल की सेना गाजा से वापस होना शुरू हो जाएगी। नई व्यवस्था फिलिस्तीन पुलिस गाजा के हाथ में होगी। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार हमास के हथियार छोड़ने के 14 दिन के भीतर वह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस समझौते की टाइमलाइन तय की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 20 सूत्रीय गाजा प्लान का यह सबसे अग्रम हिस्सा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उसमें कितना सच होता है और कितना झूठ होता है यह उनके अलावा कोई नहीं जानता है। कुछ स्थिति इजराइल की है। जब-जब इजराइल ने इस तरह के समझौते किए, जैसे ही सामने वाला पक्ष समझौते के अनुसार प्रक्रिया शुरू करता है उसके बाद उसके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। दुश्मन को अंधेरे में



रखकर हमले करने की यह रणनीति इजराइल और अमेरिका सबसे ज्यादा उपयोग में लाते हैं। यह पिछले कई वर्षों की कार्रवाई से साबित हो चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समय-समय पर पलीता लगाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। पीछे से अमेरिका भी इस रणनीति का समर्थन कर रहा था। पहले भी इजराइल और फिलिस्तीनियों तथा हमास के बीच कई समझौते हो चुके हैं। हर समझौते के बाद हमला करना इजराइल की रणनीति का हिस्सा था। इजराइल ने जिस तरह से गाज़ा में नरसंहार किया है, महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों को मौत के घाट में उतारा है। वहां पर लोग भूखे मर गए। इजराइल ने वहां रसद नहीं जाने दिया। इन सब बातों को देखते हुए ट्रंप ने जो दावा किया है वह कितना सही है, कहना मुश्किल है। जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ, उसमें खाडी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को जो नुकसान पहुंचा है, इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है, इससे साफ है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दिन में तारे दिखा दिए हैं।

ऐसी स्थिति में अमेरिका और इजराइल को अब नई रणनीति अपनाना पड़ रही है।

अमेरिका और इजराइल अब हमास से भी बात कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों से भी बात कर रहे हैं। इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने में उन्हें कई वर्ष लगेंगे। वर्तमान स्थिति में ईरान अमेरिका इजराइल फिलिस्तीन हमास खाडी के सभी देश लगातार

नुकसान से अब घबरा चुके हैं। लड़ने के लिए किसी के पास शक्ति नहीं बची है, जो कुछ शक्ति है वह वर्तमान में ईरान के पास है। ईरान को रूस और चीन का सहयोग मिला है। हार्मोज ईरान के लिए वरदान साबित हुआ है। पिछले पांच दशक से ईरान को सबने मिलकर प्रतिबंध की आड़ में कमजोर करने का हर संभव प्रयास कर लिया। अब समय बदल गया है। ईरान अब मुख्य भूमिका में है। रूस और चीन से जो समर्थन उसको मिल रहा है, उसके बाद अमेरिका और इजराइल के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि वह शांति की ओर आगे बढ़े लेकिन अभी भी वह बदमाशी करेगे तो इसका दुष्परिणाम इस बार उन्हें भारी पड़ने वाला है। ईरान पूरी तरह से सजग है। ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ का आतंक सारी दुनिया के देशों में फैलाया था, उससे अमेरिका की विश्वसनीयता और डोनाल्ड ट्रंप के रोजाना नए-नए झूठ बोलने से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सहज रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है। आशा है डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो समझौता करने जा रहे हैं, उसे ईमानदारी के साथ लागू करें। तभी दुनिया में शांति स्थापित होगी। अमेरिका और इजराइल मैं भी शांति बनी रहेगी।

क्या आप जानते हैं, घर के मुख्यद्वार के सामने कौन से पेड़ हो कौनसे नहीं



वास्तु और फेंगशुई के अनुसार घर में छोटे-छोटे और कुछ विशेष पेड़ पौधों को लगाना अच्छा माना जाता है तुलसी और बेंबु, मनीप्लांट, अपराजिता, जैसे कई पौधे हैं जिन्हे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है लेकिन कुछ ऐसे पेड़ या पौधे भी होते हैं जिसे घर के सामने होना अच्छा नहीं माना जाता है। कई घरों के मुख्य द्वार के सामने कैक्टस के छोटे पौधे लगा देते हैं, चाँदनी बेल या मनीप्लांट लगा देते हैं, जिससे मुख्य द्वार में अवरोध पैदा हो जाता है।

इस प्रकार के घर में भी बाधा का कारण बनता है। मुख्य द्वार के सामने या अंदर की ओर कोई

नुकीली चीज हो तो वहाँ रहने वालों को कोई न कोई बाधा आती रहेगी। इसी प्रकार यदि घर के सामने बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर लगा हो तो आपके यहाँ अच्छी ऊर्जा आने के बजाय निगेटिव ऊर्जा आएगी, जिसके कारण उस घर में रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव होगा। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा।

पूर्व में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। अकारण भय व धन की हानि होती है। आग्नेय में अनार का पेड़ अति शुभ परिणाम देने वाला होता है। दक्षिण में गुलर का पेड़ शुभ रहेगा। नैऋत्य में इमली शुभ रहती है। दक्षिण नैऋत्य में

जामुन और कदंब का पेड़ शुभ रहता है। उत्तर में पाकड़ का पेड़ लगाना ठीक रहेगा। ईशान में आँवला का पेड़ अति फलदायी रहता है। ईशान-पूर्व में आम का पेड़ शुभ रहता है। इस प्रकार हम पेड़ लगाकर शुभाशुभ फल प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य द्वार के सामने कोई रास्ता द्वार की ओर जा रहा हो तब भी बाधा का कारण बनता है। ग्रह स्वामी की अकाल मृत्यु हो सकती है। घर के सामने बड़ा वृक्ष रहे तो वहाँ रहने वालों की प्रगति में बाधा का कारण बनता है। यदि उस वृक्ष की छाँव घर पर पडती हो तो नुकसानप्रद रहता है। जबकि उसकी छाया कहीं से भी मकान पर नहीं पडती हो तो हानि नहीं होगी। कई जगह बंगलों में या घरों के सामने लंबे अशोक वृक्ष लगा दिए जाते हैं, जिससे घर में आड सी हो जाती है। यहाँ भी घर में रहने वालों की प्रगति के मार्ग में बाधा का कारण बनता है। जहाँ तक हो सके मुख्य द्वार को बाधा से रहित ही रखना चाहिए।



जब किस्मत साथ न दे तो सुख सौभाग्य प्राप्ति को करें यह उपाय

घर में स्थापित देवी- देवताओं को रोज फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हो। सच्चे मन से देवी- देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं व साधक का भाग्य चमका देते हैं।

घर को साफ-स्वच्छ रखें- प्रतिदिन सुबह झाड़ू-पोछा करें। शाम के समय घर में झाड़ू-पोछा न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और साधक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है।

यदि आपको भी पूरी मेहनत के बाद उचित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो प्रतिदिन सुखे आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। ऐसा नियमित रूप से प्रतिदिन करें। गाय को सभी शास्त्रों के अनुसार पूजनीय एवं पवित्र माना गया है। गाय में ही सभी देवी-देवताओं का वास है और इसकी पूजा करने से भक्त को भाग्य का साथ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गौमाता को संतुष्ट करनेपरवे सेवक को से वाके प्रतिफल में आशीर्वादस्वरूपसभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। गाय को सूखे आटे में हल्दी मिलाकर खिलाने से वे अतिप्रसन्न होती हैं। हमेशा अच्छे कर्म करो, अपने धर्म का पालन करो किस्मत के बारे मे तो मे हर मनुष्य थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, कहते हैं जब हम कडे परिश्रम करने के बाद सफलता प्राप्त करते है तो वह हमारे कर्म है लेकिन जब हम बिना मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त करते हैं उसे किस्मत

कहते है। ब्रहम बेला में उठ कर इश्वर का नाम, ध्यान, योग और पूजा करने से अकस्मात् लाभ होता है। सूर्योदय से पूर्व ब्रहमा बेला में उठे, और अपने दोनों हांथों की हथेली को रागरे और हथेली को देख कर अपने मुंह पर फेरें, क्योंकि :- शास्त्रों में कहा गया है की कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती। करमूले स्थिता गौरी, मंगलं करदर्शनम् ॥ हमारे हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, तथा हाथ के मूल मे सरस्वती का वास है अर्थात भगवान ने हमारे हाथों में इतनी ताकत दे रखी है, जिसके बल पर हम धन अर्थात लक्ष्मी अर्जित करते हैं। जिसके बल पर हम विद्या सरस्वती प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं सरस्वती तथा लक्ष्मी जो हम अर्जित करते हैं, उनका समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभू स्वयं हाथ के मध्य में बैठे हैं। ऐसे में क्यों न सुबह अपने हाथ के दर्शन कर प्रभू की दी हुई ताकत का लाभ उठायें।। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्म का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे।

नवग्रहों की अद्भुत शक्तियां



नवग्रहों में अद्भुत शक्तियां हैं जिसके कारण इसे देवताओं के समान आदर दिया गया है। यह दवा की भांति व्यक्तियों को पीडा से उबारने में सक्षम होता है। इनमें कमजोर ग्रहों को बलवान बनाने की क्षमता होती है जिससे असंभव को भी संभव करने में भी राशि रत्न कारगर होते हैं।

पुखराज की ज्योतिषीय विशेषता

बृहस्पति ग्रह का रत्न पुखराज पीली आभा लिये होता है। यह गहरा पीला, हल्का पीला एवं सफेद भी होता है। छूने में ठोस, चिकना, चमकीला, दाग धब्बा रहित पुखराज उत्तम होता है। दूध में रात भर रखने से असली पुखराज क्षीण नहीं होता है और न ही इसका रंग फीका होता है। पुखराज धारण करने से पहले अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए कि रत्न दोष रहित हो।

पुखराज धारण करने से लाभ

जिस व्यक्ति की कुण्डली में बृहस्पति नीच का होता है अथवा कमजोर होता है उनके लिए पुखराज धारण करना लाभप्रद होता है। पुखराज अध्यात्म, सत्यता, लनशीलता और सजगता का प्रतीक होता है। प्रेमियो के लिए यह भाग्यशाली रत्न माना जाता है। मानसिक शांति एवं आत्मिक शांति के लिए भी यह रत्न लाभकारी होता है। इस रत्न को धारण करने से वाणी सम्बन्धी दोष एवं गले की पीडा से राहत मिलती है। प्राचीन यूनान में इसे अपोलो देवता द्वारा प्रदान किया गया माना जाता था जिसका उपयोग कई प्रकार के रोगों

के ईलाज के लिए किया जाता था। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जिस कन्या की शादी में बार बार बाधा आ रही हो वह अगर पुखराज धारण करती हैं तो विवाह में बाधक तत्व का अंत होता है और जल्दी शादी होती है।

हीरा की ज्योतिषीय विशेषता हीरा संसार का सबसे कठोर रत्न है। इसे किसी भी अन्य रत्न से खरोंचा नहीं जा सकता। हीरा जितना कठोर व चमकीला होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। यह मुख्यतः सफेद, पीला , लाल, गुलाबी और काला होता है। मान्यताओं के अनुसार संतान की इच्छा रखने वाली महिलाओं को हीरा धारण नहीं करना चाहिए। ज्योतिषशास्त्र इस मान्यता को नही स्वीकार करता है। ज्योतिषशास्त्र के नियमानुसार जो स्त्री त्रिकोण हीरा धारण करती हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।

हीरा धारण करने से लाभ

हीरा शुक्र का रत्न है। तुला और वृषभ राशि वाले अगर इस रत्न को धारण करते हैं तो उनका शुक्र मजबूत होता है फलतः शुक्र से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में उन्हें लाभ मिलता है। जिनकी

कुण्डली में शुक्र कमजोर अथवा मंदा है उन्हें भी हीरा धारण करने से लाभ मिलता है। हीरा की विशेषता है कि इसे धारण करने वाला व्यक्ति साहसी, बुद्धिमान और उत्साही होता है। हीरा कई प्रकार के मानसिक रोगों में लाभकारी होता है। यह जहर काटने में भी सक्षम होता है। हीरा धारण करने वाले पर जादू टोने का प्रभाव नहीं होता है। रंग के अनुसार हीरा का अलग अलग प्रभाव होता है जैसे लाल और पीला हीरा राजनीति और प्रशासन से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है। सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए सफेद हीरा उत्तम होता है।



कुछ ऐसी चीजें जिन्हें घर में रखने से कभी नहीं होती पैसों की कमी

अगर आप धन संबंधी परेशानियों को लेकर चिंतित रहते हैं तो इसका कारण आपके घर में मौजूद वास्तुदोष हो सकता है। इस दोष से मुक्ति और धन-सुख के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें घर में रखने से धन संबंधी सभी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं और घर में हमेशा धन-धान्य बना रहता है।

धातु के बने कछुए और मछली को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। घर के जिस हिस्से में परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वहां पर चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड

रखें। यह घर के सदस्यों की आय में वृद्धि करता है। घर की उत्तर दिशा में पानी से भरी सुराही रखनी चाहिए। इससे घर में धन की कमी नहीं होती। सुराही न हो तो मिट्टी का घड़ा रखा जा सकता है। ये कभी भी खाली न रहे, पानी खत्म हो जाने पर इसे फिर से भर दें। घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में भगवान हनुमान की पंचस्वरूप वाली मूर्ति या तस्वीर लगाएं। नियमित रूप से उनकी पूजा करें। घर के मेन गेट पर देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर या स्वास्तिक का चिन्ह या फोटो लगाने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। घर में वास्तु भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखने से घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती।



कोशिशों के बाद भी आप किसी काम में बार-बार असफल हो रहे हैं या मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में किस्मत या भाग्य का साथ न होने की बात कही जाती है। ज्यादा धन या पैसा कमाने के लिए किस्मत का साथ होना बहुत जरूरी है अन्यथा इस मनोकामना की पूर्ति होना असंभव सा ही है। ज्योतिष में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से दुर्भाग्य पीछा छोड़ देता है और भाग्य साथ देने लगता है। जब किस्मत साथ न दे तो करें यह उपाय इस छोटे से उपाय द्वारा बदकिस्मत लोगों की भी किस्मत साथ देने लगेगी ।

मनोवाछित फल की प्राप्ति के लिए कीजिए यह व्रत

मां ललिता

महाविद्याओं में से एक हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मां ललिता का व्रत किया जाता है। इस व्रत को उपांग ललिता व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष उपांग ललिता व्रत 17 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन है।

मां ललिता की उत्पति:

उपांग ललिता मां शक्ति का स्वरूप हैं। मां ललिता की उत्पत्ति तब हुई जब ब्रहमा जी द्वारा छोड़े गये चक्र से पाताल समाप्त होने लगा तब इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि-मुनि भी परेशान हो गए और संपूर्ण पृथ्वी धीरे-धीरे जलमग्न होने लगी है। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं। सृष्टि पुनः नवजीवन को पाती है।

मां ललिता का स्वरूप:

कालिकापुराण के अनुसार देवी की दो भुजाएं

हैं, यह गौर वर्ण की, रक्तिकमल पर विराजित हैं। ललिता देवी की पूजा से समृद्धि की प्राप्त होती है। दक्षिणमार्गी शाक्तों के मतानुसार देवी ललिता को चण्डो का स्थान प्राप्त है। इनकी पूजा पद्धति देवीचण्डो के समान ही की जाती है।

व्रत का महत्व:

उपांग ललिता व्रत करने से मां उपांग ललिता का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक मान्यतानुसारइसदिन देवीललिता ने एक दानव लियाथा।इसदिन भक्तगण षोडशोपचार विधि से मां ललिता का पूजन करते हैं। इस दिन मां ललिता के साथ साथ स्कंदमाता और शिव शंकर की भी शास्त्रानुसार पूजा की जाती है। ऐसे करें पूजन: शक्तिस्वरूपा देवी ललिता को समर्पित उपांग ललिता पंचमी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को पंचम नवरात्र के दिन मनाई जाती है। इस शुभ दिन भक्तगण व्रत एवं उपवास का पालन करते हैं, यह दिन उपांग ललिता व्रत के नाम से जाना जाता है।



क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को वामन रूप में जन्म

दैत्यों का राजा बलि बड़ा पराक्रमी राजा था। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसकी शक्ति के घबराकर सभी देवता भगवान वामन के पास पहुंचे तब भगवान विष्णु ने अदिति और कश्यप के यहाँ जन्म लिया। एक समय वामन रूप में विराजमान भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पहुंचे उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा थे। बलि से उन्होंने कहा राजा मुझे दान दीजिए। बलि ने कहा-मांग लीजिए। वामन ने कहा तीन पग मुझे आपसे धरती चाहिए। दैत्यगुरु भगवान की महिमा जान गए। उन्होंने बलि को दान का संकल्प लेने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने कहा - गुरुजी ये क्या बात कर रहे हैं आप।

यदि ये भगवान हैं तो भी मैं इन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। बलि ने संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने अपने विराट स्वरूप से एक पग में बलि का राज्य नाप लिया, एक पैर से स्वर्ग का राज नाप लिया। बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। तब भगवान ने कहा तीसरा पग कहां रखूँ। बलि ने कहा-

-मेरे मस्तक पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान ने उसके ऊपर पग धरा राजा बलि पाताल में चले गए। भगवान ने बलि को पाताल का राजा बना दिया। सतयुग में दैत्यराज प्रहाद के पोत्र बलि ने स्वर्ग में अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा की मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को भगवान विष्णु ने अपने गुरु शुक्राचार्य और मुनियों के साथ दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया।

बलि के इस महायज्ञ में ब्रह्मचारी वामन जी भी गए। वे अपनी मुस्कान से सब लोगों के मन मोह लेते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपो बल से वामन के रूप में अवतरित भगवान

विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को बताया की तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने भगवान विष्णु वामनरूपी अवतार में आये है। गुरुदेव की बातों को सुन कर राजा बलि ने कहा हे गुरुदेव आप क्यों धर्म विरोधी वचन कह रहे है, भगवान विष्णु मुझ से दान मांगने आये है इस से बढ़कर और क्या हो सकता है। मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह यज्ञ कर रहा हूँ। यदि भगवान विष्णु स्वयं पधारे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। तभी वामनजी बलि के यज्ञशाला में पधारे, उन्हें देख राजा बलि अपने दोनों हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो गए और कहा, हे प्रभु मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिये तब वामन भगवान ने उनसे तीन पग भूमि मांगी और कहा भूमिदान का महात्सव महान है।

राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु की लीला समझ गए और उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया। लेकिन फिर भी बलि ने भूमि दान के संकल्प के लिए कलश उठाया परन्तु गुरु शुक्राचार्य उस कलश में घुस गए।

भगवान विष्णु यह जान गए की गुरु शुक्राचार्य कलश में घुसकर जल की धारा को रोक रहे है। अतः उन्होंने कुश के अग्र भाग को कलश के मुख में घुसेड़ दिया जिसने गुरु शुक्राचार्य की एक आँख को नष्ट कर दिया। पीडा से व्याकुल होकर गुरु शुक्राचार्य उस कलश से बाहर निकले।

तब बलिन ने तीन पग दान का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण कर पहले एक पग पूरी धरती को नाप लिया तथा अपने दूसरे पग में उन्होंने पुरे स्वर्गलोक को नापा। जब तीसरे पग के रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। वामन भगवान ने उन्हें भय दिखाया की यदि तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो ये अधर्म होगा। तब तीसरे पग के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए राजा बलि ने अपना सर उनके पग के नीचे रख लिया। वामन भगवान के तिसरा पग रखते ही बलि पाताललोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देख वामनरूप भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया और इस तरह भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्गलोक सौंपा।

नीट पीजी-एक ही शिफ्ट में पेपर

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2026 परीक्षा के लिए कई बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसमें परीक्षार्थियों की यात्रा और परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इस बार परीक्षा 30 अगस्त को होनी है। इसके लिए 2.73 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में 12.57 ज्यादा है। परीक्षा देशभर के 340 शहरों के लगभग 1300 सेंटर्स पर होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक से सबक लेते हुए परीक्षा के पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा पुख्ता करना शुरू कर दिया है। इसके लिए 7.5 करोड़ का टेंडर जारी किया है। इसमें एनटीए मुख्यालय समेत संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे सिक्योरिटी दी जाएगी। यह टेंडर 25 जुलाई को जारी हुआ है। 17 अगस्त को बोलियां खोली जाएंगी।आधार की जांच: आवेदन और एग्जाम के दिन आधार आधारित वैरिफिकेशन होगा। बायोमीट्रिक जांच होगी। इसके लिए छात्रों को 2-3 घंटे पहले सेंटर पहुंचना होगा। फिंगरप्रिंट न मिलने पर आईरिस (आंखों की पुतली) स्कैन की जाएगी।

गोली मारो टिप्पणी मामला अनुराग ठाकुर को राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गोली मारोटिप्पणी मामले में अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर माकपा नेता वृंदा करात की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के कथित गोली मारो भाषण के मामले में एफआईआर दर्ज कराने से इनकार करने वाले 29 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा किपहले दिए गए फैसले पर दोबारा विचार करने का कोई आधार नहीं बनता। 29 जुलाई को पारित आदेश में पीठ ने कहा, हमने पुनर्विचार याचिका और उसके समर्थन में दिए गए आधारों का अध्ययन किया है। हमें आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली, विशेष रूप से ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं, जिसके आधार पर इस पर पुनर्विचार किया जाए।

दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते

तुरंत मौके पर पहुंचे और गहन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस का कहना है कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और परिसर की गहन जांच की जा रही है। अब तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार, अलग-अलग स्कूलों को धमकी भरे संदेश मिले, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमों के साथ दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंच गए और स्कूल परिसरों की गहन तलाशी शुरू की गई। जांच में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।

महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू

मुंबई। महाराष्ट्र में जबरन, धोखाधड़ी, लालच या शادی के झांसे से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए नया कानून लागू हो गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 को ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित कर दिया है. महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों ने इस साल मार्च में बजट सत्र के दौरान महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 2026 पारित किया था. राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 30 जुलाई को इसे राज्य के राजपत्र में नोटिफाई कर दिया गया. इसके साथ ही अब राज्य में ये कानून प्रभावी हो गया है. नए कानून के प्रावधानों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरा धर्म अपनाना चाहता है, तो उसे धर्मांतरण से कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी. इसके साथ ही धर्मांतरण के बाद की तय प्रक्रियाओं का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है. अधिनियम के तहत बल, दबाव, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, गलत बयानी या शادی से जुड़े धोखे के जरिए कराए गए धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध बनाया गया है।

गुजरात: चांदीपुरा वायरस से अब तक 22 बच्चों की मौत

नईदिल्ली। गुजरात में भारी बारिश के बीच चांदीपुरा वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य में अब तक इस वायरस से जुड़े 184 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से जांच के बाद 35 मरीज चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 11 नमूनों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है. राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए स्वास्थ्य तंत्र को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है और सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने बताया कि अब तक सामने आए सभी संदिग्ध मामले चांदीपुरा वायरस के नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जांच में 35 मामले ही पॉजिटिव पाए गए हैं. अब तक चांदीपुरा वायरस से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य के विभिन्न सिविल अस्पतालों में सात संक्रमित बच्चों का इलाज चल रहा है, जबकि छह संक्रमित बच्चों की हाात में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गांधीनगर, साबरकांठा के हिम्मतनगर, पाटन, राजकोट और भावनगर के सिविल अस्पतालों में भर्ती बच्चों को सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में इलाज दिया जा रहा है।

संसद में विपक्ष के हंगामे का एनडीए ने निकाला तोड़

‘मंगल मिलन’ बैठक में बनाया गया मास्टर प्लान



संसदीय रणनीति और सरकार के एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर रहा।

हम आपको यह भी बता दें कि हाल के दिनों में इस बैठक का नाम ‘मंगल मिलन’ रखा गया है और अब यह एनडीए के संसदीय समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण मंच बन चुकी है। संसद सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को होने वाली इस बैठक में सरकार के विधायी एजेंडे, सदन में विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का रुख, सांसदों की भागीदारी और सहयोगी दलों की भूमिका तय की जाती है। शिवसेना, जनता दल (यूनाइटेड), तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जद(एस), राष्ट्रवादी सहयोगी दलों सहित सभी घटकों के बीच बोलने की जिम्मेदारियां भी इसी मंच पर बांटी जाती हैं ताकि सदन में सरकार का पक्ष एकजुट और प्रभावी ढंग से रखा जा सके।

हम आपको बता दें कि मंगलवार की बैठक का एक बड़ा हिस्सा सरकारी

की उपलब्धियों को सांसदों तक विस्तार से पहुंचाने पर केंद्रित रहा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेल क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 2014 में अपनाई गई नई खेल नीति के बाद भारत ने ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है और स्वर्ण पदकों सहित कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार का उद्देश्य इन उपलब्धियों को केवल खेल तक सीमित नहीं रखना, बल्कि इन्हें नए भारत की बदलती तस्वीर के रूप में जनता तक पहुंचाना भी है।

रोजगार के मुद्दे पर भी सांसदों के सामने विस्तृत आंकड़े रखे गए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि बैठक में यह जानकारी साझा की गई कि 2004 से 2014 के बीच संगम सरकार के कार्यकाल में जहां केवल 2.89 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, वहीं 2014 से 2026 के बीच

लगभग 17.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और उनके प्रभाव पर भी विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया गया ताकि सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में इन तथ्यों के साथ जनता के बीच जा सकें।

बैठक में एनडीए के भीतर बहते समन्वय की झलक भी दिखाई दी। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मंगल मिलन में मंगल ही होता है। वहीं तुणमूल कांग्रेस छोड़कर एनसीपीआई में आए वरिष्ठ सांसद सुदीप बघोपाध्याय पहली बार इस बैठक में शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि वह देश के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं और एनसीपीआई पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने एनडीए की इस संगठित कार्यप्रणाली को सकारात्मक अनुभव बताया। इससे पहले ही एनसीपीआई के सांसदों ने एनडीए की संसदीय व्यवस्था और अनुशासित प्रणाली की सराहना की थी।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह बैठक विपक्ष की रणनीति के जवाब में एनडीए की जवाबी चाल भी थी। जहां विपक्ष सदन नहीं चलने देने की रणनीति पर कायम है, वहीं सरकार अब हर मुद्दे पर तथ्य, आंकड़े और समन्वित संसदीय प्रबंधन के साथ मैदान में उतरने जा रही है। यही वजह है कि अगले दस दिनों के लिए फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है, ताकि विधेयकों को पारित कराने के साथ-साथ हर बहस में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जा सके।

सैंसेक्स 210 अंक टूटा निफ्टी 24,615 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को चार कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। बैंकिंग, वित्तीय और आईटी शेयरों में बिकवाली के दबाव के चलते प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं, निवेशकों ने बुधवार को आने वाले भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के फैसले से पहले सतर्क रुख अपनाया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 210.08 अंक यानी 0.27 फीसदी की गिरावट के साथ 78,428.95 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 159.40 अंक यानी 0.64 फीसदी टूटकर 24,614.90 के स्तर पर बंद हुआ। पूरे कारोबारी सत्र के दौरान बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और आईटी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। इसका असर बाजार के प्रमुख सूचकांकों पर साफ दिखाई दिया। निवेशकों ने भी आरबीआई की ब्याज दरों पर होने वाली घोषणा से पहले नए निवेश से दूरी बनाए रखी।

गोदरेज प्रॉपर्टीज का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 42% घटा

नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 42 प्रतिशत घटकर 349.38 करोड़ रुपए रह गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 598.40 करोड़ रुपए था। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय भी घटकर 1,345.04 करोड़ रुपए रह गई जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,620.34 करोड़ रुपए थी। परिचालन मोर्चे पर गोदरेज प्रॉपर्टीज की चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में बिक्री बुकिंग 22 प्रतिशत बढ़कर 8,651 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 62 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली 3,738 इकाइयों की बिक्री की।

अडानी इंफ्रा ने अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.03% हिस्सेदारी खरीदी

नई दिल्ली। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) की प्रवर्तक समूह की कंपनी अडानी इंफ्रा (इंडिया) लिमिटेड ने कंपनी में 2,380 करोड़ रुपए में 1.03 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। एनएसई पर मौजूद सौदे के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। अडानी इंफ्रा (इंडिया) लिमिटेड ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के 1.7 करोड़ शेयर खरीदे जो कंपनी की 1.03 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। ये सौदे सोमवार को 1,400 रुपए प्रति शेयर के औसत मूल्य पर किए गए। इस तरह कुल सौदे का आकार 2,380 करोड़ रुपए रहा। आंकड़ों के अनुसार, विक्रेता एजीईएल की प्रवर्तक कंपनी आईर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड थी जिसने समान मूल्य पर इतनी ही संख्या में शेयर बेचे। इस सौदे के बाद नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी में अडानी इंफ्रा की हिस्सेदारी बढ़कर 2.34 प्रतिशत हो गई, जो पहले 1.31 प्रतिशत थी।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का मुनाफा 3 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने बताया कि जून, 2026 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर तीन प्रतिशत बढ़कर 873 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 845 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने शेयर बाजार को बताया कि जून तिमाही में उसकी कुल आय पांच प्रतिशत बढ़कर 1,385 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1,324.8 करोड़ रुपए थी। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च 8% बढ़कर 242 करोड़ रुपए हो गया। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने समीक्षाधीन तिमाही के दौरान 15.1% को बाजार हिस्सेदारी के साथ देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड प्रबंधक के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा।

खेल प्रमुख समाचार

नीरज चोपड़ा अब लुसाने डायमंड लीग में आएंगे नजर



नई दिल्ली। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा 21 अगस्त को लुसाने डायमंड लीग में राष्ट्रमंडल चैंपियन और इस सत्र में सबसे आगे चल रहे श्रीलंका के रूमेश पथिरागे का सामना करना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले चुके पांच खिलाड़ी नजर आएंगे। ग्लासगो में सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 85.83 मीटर का थ्रो फेंकने वाले चोपड़ा का सामना ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नवीम, मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केशॉन वालकराट और पूर्व विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स से होगा। तोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता चेक गणराज्य के याकूब वालेश, जर्मनी के जूलियन वेबर, स्विटजरलैंड के सिमोन विलेंड और अमेरिका के कुर्टिस थॉम्पसन भी इसमें नजर आएंगे।

आयोजकों ने कहा, %पिछले चार ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जीत चुके भाराफेंक के पांच सुपरस्टार 21 अगस्त को इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। % चोट से उबरने के बाद यह चोपड़ा का तीसरा टूर्नामेंट होगा। वह जून में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। पथिरागे ने राष्ट्रमंडल खेलों में 89.75 मीटर का थ्रो लगाकर पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने जून में गोल्डन गला पिप्टो मैरिया में 92.62 मीटर का थ्रो लगाया था।

रवींद्र चोपड़े

चार साल बाद अहमदाबाद में मिलने के वादे के साथ ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन हो गया। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, महिला क्रिकेट और स्कैश जैसे भारत के लिहाज में 'उपजाऊ' खेलों को ग्लासगो में शामिल नहीं किया गया था। मेजबान ग्लासगो ने 'कॉस्ट कटिंग' के लिए इन खेलों को हटाया था, इसके बावजूद भारत ने मुक्केबाजों के अद्वितीय पराक्रम से 13 स्वर्ण समेत कुल 39 पदक अपनी झोली में डाले। एथलेटिक्स, तैराकी, ट्रैक साइकिलिंग, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, जूडो, लॉन बॉल्स, नेटबॉल, कलात्मक जिम्नास्टिक्स और 3×3 बास्केटबॉल इन खेलों में शामिल थे।

मूल रूप से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को मिली थी। लेकिन आयोजन पर क़रीब सात

अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की लागत देख विक्टोरिया ने 2023 में ही इससे हाथ खींच लिए थे। आखिरकार ग्लासगो को वैकल्पिक मेजबान चुना गया। ग्लासगो ने भी लागत कम करवाने के लिए कुछ बड़े खेलों को हटा दिया और आयोजन में नए स्टेडियम या खेल गांव वगैरह का निर्माण करने के बजाय उन्हीं संरचनाओं का इस्तेमाल किया जो उसने 2014 में इन खेलों की मेजबानी करते हुए तैयार की थीं।

बहरहाल, ग्लासगो 2026 को भारत के लिए कम पदकों वाला खेल नहीं, बल्कि कम अवसरों वाला राष्ट्रमंडल खेल कहना ज्यादा उचित होगा। भारत ने 39 पदक जीतकर उपलब्ध अवसरों का अच्छा इस्तेमाल किया। भारत के यह पदक 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के बनिबख्त 22 कम हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन मेजबान होने के नाते 2010 में रहा था जब



उसने कुल 101 पदक जीते थे। उम्मीद की जा रही है कि 'कॉस्ट कटिंग' के नाम पर जिन खेलों को ग्लासगो में सूची से हटा दिया गया था उनकी 2030 अहमदाबाद खेलों में वापसी होगी।

हालांकि अभी सभी खेलों की अंतिम

सूची घोषित होने में विलंब है लेकिन जो जानकारीयां फिलवक्त हैं उनके अनुसार 2030 में 15 से 17 खेल होंगे। भारत के लिहाज से क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग और कुश्ती सबसे महत्वपूर्ण वापसी होगी। खासकर शूटिंग और कुश्ती में भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में शाहद

रिकॉर्ड रहा है, जबकि हॉकी और क्रिकेट में टीम पदक की मजबूत दावेदार रहती है। बैडमिंटन और टेबल टेनिस भी भारत की पदक उम्मीदों के लिहाज से बेहद अहम हैं।

इसके अलावा भारत अहमदाबाद में अपने पारंपरिक खेलों को भी शामिल कराने की कोशिश कर सकता है। योगासन, कबड्डी, खो-खो और मल्लखंब जैसे खेलों को लेकर चर्चा है यानी 2030 का राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए सिर्फ ग्लासगो में खूटे खेलों की वापसी नहीं, बल्कि भारतीय खेलों को नया मंच देने का अवसर भी हो सकता है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के पूरे कार्यक्रम की घोषणा अगले साल होगी लेकिन अब असली चुनौती मेजबानी की लागत को लेकर है। वैश्विक आर्थिक स्थिति कई जगों के कारण बहुत अच्छी नहीं है और शायद आगे और बढ़तर हो। ऐसे में चार साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी भारी लागत काफ़ी हो सकती है।

कलश वंदन महाअभियान : रविदास जयंती पर रहेगी छुट्टी मुख्यमंत्री साय ने की घोषणा

संत रविदास ने समाज को नई चेतना प्रदान की

रायपुर। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज का जीवन समरसता, समानता, भक्ति, ज्ञान और सामाजिक न्याय का अमर संदेश है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने सदियों पहले थे। संत रविदास ने समाज को ऊंच-नीच, भेदभाव और छुआछूत से ऊपर उठकर मानवता, समान अधिकार और आध्यात्मिक चेतना का मार्ग दिखाया। यही मार्ग विकसित, समरस और सशक्त भारत की आधारशिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कलश वंदन महाअभियान के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से लाए गए पवित्र मिट्टी एवं जल से भरे



कलश को श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर संत रविदास के छायाचित्र के समक्ष स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन-अर्चन कर संत रविदास को नमन किया तथा इसे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने संत रविदास के सम्मान में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में अगले वर्ष 2027 में उनकी

जयंती (माघी पूर्णिमा) को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेशभर में मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर प्रदान किए जाने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कारों में संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम से एक राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नामकरण भी संत गुरु रविदास के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में संत रविदास के प्रसिद्ध

संदेश –

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत संतों, ऋषियों और महापुरुषों की पावन भूमि है। जब-जब समाज में अन्याय, अत्याचार, ऊंच-नीच, छुआछूत और भेदभाव जैसी विकृतियां बढ़ीं, तब-तब संतों और महापुरुषों ने समाज को नई दिशा प्रदान की। संत रविदास ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता और भक्ति का ऐसा संदेश दिया, जिसने समाज को नई चेतना प्रदान की। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने तत्कालीन शासक सिकंदर लोदी के धर्मांतरण के दबाव का भी साहसपूर्वक विरोध किया और यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं तथा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल सच्ची भक्ति और सदाचार है। उनका प्रसिद्ध संदेश मन चंगा तो कठौती में गंगा आज भी समाज को आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने संत रविदास से जुड़ा प्रसंग भी साझा किया और कहा कि उनकी अदृष्ट भक्ति और तपस्या के प्रभाव से कठौती में गंगा प्रकट होने की घटना केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह संदेश है कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का विकास भी, विरासत भी का संदेश देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण का मार्गदर्शक मंत्र है। उन्होंने कहा कि संत रविदास की जन्मभूमि से लाई गई पवित्र मिट्टी और जल का कलश देशभर के मठों, मंदिरों और आस्था केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। यह समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार को जोड़ने वाला राष्ट्रीय समरसता अभियान है।

मेकाहारा के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (मेकाहारा) के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण हड़ताल शुरू कर दी है। आंदोलन के पहले दिन इंटर्न डॉक्टरों ने शहर में बाइक रैली निकालकर राज्य सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया।

डॉक्टरों की मुख्य मांग वर्तमान में मिलने वाले 15,900 रुपये मासिक स्ट्राइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की है। मेकाहारा परिसर से शुरू हुई बाइक रैली देवेंद्र नगर चौक, घड़ी चौक और मरीन ड्राइव से होकर पुनः चिकित्सा महाविद्यालय परिसर पहुंची। रैली के दौरान इंटर्न डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रखा और सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई और आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया गया। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस इंटर्न्स को मिलने वाला



स्ट्राइपेंड देश के कई राज्यों की तुलना में काफी कम है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में इंटर्न डॉक्टरों को लगभग 43 हजार रुपये प्रतिमाह, ओडिशा में करीब 42 हजार रुपये और बिहार में लगभग 27 हजार रुपये मासिक स्ट्राइपेंड दिया जाता है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी 30 हजार से 45 हजार रुपये तक का स्ट्राइपेंड दिया जा रहा है।

ऐसे में छत्तीसगढ़ के इंटर्न डॉक्टर भी अपने कार्यभार और जिम्मेदारियों के अनुरूप सम्मानजनक स्ट्राइपेंड की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पतालों में इंटर्न डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। वे नियमित रूप से 24-24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं और कई बार लगातार ड्यूटी पूरी करने के बाद भी ओपीडी में मरीजों की सेवा देते हैं।

बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था के कारण कांग्रेस नेता की हत्या हुई: बैज

रायपुर। दुर्ग में कांग्रेस नेता की हत्या पर कांग्रेस ने आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और बढ़ता अपराध अब बर्दास्त के बाहर हो गया है। दुर्ग के जेवरा सिरसा में कांग्रेस के नेता प्रकाश कश्यप की सरेंआम घर जाते समय लूटने की नीयत से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गयी। जांजगीर-चांपा शहर में लिफ्ट मांगने के बहाने लूटने की कोशिश की गयी, विरोध करने पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी। बिलासपुर में 6 नकाबपोशों ने सरेंआम शराब दुकान में हमला कर गार्ड को बंधक बनाकर लूट लिया। यह घटनाये राज्य की बदतर हो चुकी कानून व्यवस्था के कुछ नमूना है। पूरे राज्य में अपराध



का ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि अब आदमी खुले में सड़क में चलने में डरने लगा है, नागरिक महिलायें कोई सुरक्षित नहीं हैं, कब किसकी कहाँ हत्या हो जाये कौन अपराधी कब किसको चाकू मार दे कहा नहीं जा सकता। पुलिस और सरकार दोनों अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। सक्ती में एक युवती को उसके घर में घुसकर गोली मार दी गयी। इसके पहले कोरिया के सोनहत में चार व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया। जैजपुर में दो भाइयों को घर में घुसकर गोली मार दिया गया। पेण्ड्रा के कोटमी बाजार में

सराफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रदेश में कोई जिला नहीं जहां पर रोज हत्या, लूट, बलाकार, चाकूबाजी की घटना नहीं हो रही है।

राजधानी रायपुर के ही गंज थाना क्षेत्र में सरेंआम चाकूबाजी हुई, एक युवक की हत्या हो गई, उनसे जेवरात लूट लिए गए। बिन्दानवागढ़ के देवभोग में महिला समेत परिवार के चार सदस्यों पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया, महिला की गर्दन पकड़ कर ब्लेड चला दिया गया जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, मौके पर मौजूद उनके दोनों बेटे और पति गंभीर रूप से घायल हो गये थे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 1 दर्जन से अधिक लोगों की गोली मारकर हत्या हुई।

इसरो के वैज्ञानिकों ने किया जिला विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा का भ्रमण

रायपुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर आनंद और उनकी विशेषज्ञ टीम ने जिला विज्ञान केंद्र, दंतेवाड़ा का भ्रमण कर यहां संचालित वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया।



टीम ने विज्ञान केंद्र की स्पेस गैलरी, फिजिक्स गैलरी, माइनिंग गैलरी, विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनों, बकिंग मॉडल्स और विद्यार्थियों के लिए आयोजित 'करके सीखें' गतिविधियों का निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने सुदूर जनजातीय क्षेत्र के बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और विज्ञान केंद्र की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र बच्चों को प्रयोगों और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसरो की टीम ने केंद्र प्रमुख उपेंद्र गौतम और उनकी टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की। वैज्ञानिकों ने केंद्र में नियमित रूप से आयोजित शैक्षणिक भ्रमण, 'कबाड़ से जुगाड़' विज्ञान गतिविधियां और खगोल विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन को विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाने की दिशा में प्रभावी पहल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों को विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। भ्रमण के अंत में विज्ञान केंद्र प्रबंधन ने इसरो के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। इसरो की टीम के आगमन से विज्ञान केंद्र के विद्यार्थियों, शिक्षकों और विज्ञान में रुचि रखने वाले युवाओं में उत्साह का वातावरण देखने को मिला।

पेसा और एफआरए टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम (पेसा) और वन अधिकार अधिनियम के तहत समन्वय से वनवासियों के हित में साझा जल-जंगल के बेहतर प्रबंधन से कार्य किया जाएगा। इस संबंध में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में पेसा और एफआरए टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जल, जंगल, जमीन के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन छत्तीसगढ़ राज्य हो तथा वनवासियों के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन हो इस संबंध में मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को वन अधिकार अधिनियमों के अनुसार वन संसाधन अधिकार पत्र दिए जायें। बैठक में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के क्रियान्वयन



के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

टास्क फोर्स की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, प्रावधान एवं क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसी तरह से वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में प्राप्त निराकृत एवं लॉबित दावों, आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों की मान्यता में हुई प्रगति तथा वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की प्रगति की जानकारी विभागीय अधिकारियों

ने दी।

बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियमों के क्रियान्वयन की जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी तरह से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पेसा नियम के क्रियान्वयन के संबंध में भी प्रस्तुतिकरण दिया गया।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मा शर्मा, पीसीसीएफ श्री अरूण पाण्डेय, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आंबिदी सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

नगर निगम में अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार



रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से निगम के कार्यों के सुचारु एवं प्रभावी संचालन के उद्देश्य से आगामी आदेश तक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार श्रीमती जागृति साहू, उपायुक्त को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग (जाति प्रमाण पत्र) के उपायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार श्री जसदेव सिंह बाबर, उपायुक्त को उनके वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग के उपायुक्त एवं जोन क्रमांक 2 के चेक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं श्रीमती संगीता साहू, प्रभारी उपायुक्त को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ जनसूचना अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यह आदेश नगर निगम आयुक्त द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रभावशील कर दिया गया है।

स्वास्थ्य अधोसंरचना को मिलेगी नई गति: स्वास्थ्य मंत्री

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में स्वास्थ्य अधोसंरचना को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव के साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इनमें ट्रॉमा सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, नवीन सिकल सेल इंस्टीट्यूट, बाॅयज एवं गर्ल्स हॉस्टल तथा स्टॉफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग जैसे महत्वपूर्ण निर्माण शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। बैठक में आगामी कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए, जिससे आमजन को स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर लाभ शीघ्र मिल सके।



8, 9 एवं 16 अगस्त को होगी मुद्रलेखन कौशल परीक्षा

रायपुर। शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्यूटर मुद्रलेखन कौशल परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा। परिषद के अनुसार 08 अगस्त 2026 को अंग्रेजी कम्प्यूटर मुद्रलेखन (गति 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा) की परीक्षा प्रदेश के 08 परीक्षा केन्द्रों पर, 09 अगस्त 2026 को हिन्दी कम्प्यूटर मुद्रलेखन (गति 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा) की परीक्षा 09 परीक्षा केन्द्रों पर तथा 16 अगस्त 2026 को बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग में एक-एक परीक्षा केन्द्र पर आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों के लिए परिषद द्वारा आर्बाइट परीक्षा केन्द्र, निर्धारित बैच एवं समय पर परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <https://ctsp.cg.nic.in> पर उपलब्ध है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी सूचना परीक्षार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के समय पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा मतदाता परिचय पत्र में से कोई एक मूल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रवेश पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत छात्राओं को किया गया जागरूक

रायपुर। राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरगुजा जिले के विभिन्न विद्यालयों में छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) संक्रमण, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम तथा एचपीवी टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। अभियान के अंतर्गत दशमेश पब्लिक स्कूल की 60, कार्मेल स्कूल की 125 तथा होली क्रॉस स्कूल की 310 छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्राओं को बताया कि एचपीवी वैक्सिन गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर से बचाव का सुरक्षित एवं प्रभावी माध्यम है। समय पर टीकाकरण कराने से इस गंभीर बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने टीकाकरण से जुड़े लाभ, आवश्यक सावधानियों एवं भावित्यों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें अपने अभिभावकों एवं परिवार के अन्य सदस्यों को भी एचपीवी टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले की सभी पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से अपील की है।

40 से अधिक लोगों ने रक्तदान करने दोस्ती की मिसाल पेश की



रायपुर। शहर की संस्था नेकी कर फाउंडेशन द्वारा दोस्ती के पवित्र दिन दोस्ती दिवस पर रक्तदान शिविर और जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया। एक रक्तदान , देश के नाम इस आयोजन में संस्था नेकी कर फाउंडेशन द्वारा शहर वासियों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया और रक्तदान से होने वाले फायदे को जागरूक किया गया। यह रक्तदान तेलीबंद तालाब मरीन ड्राइव में आयोजित किया गया जिसमें 20 से अधिक कार्यकर्ता ने सेवा दी एवं 40 से अधिक लोगों ने रक्तदान करने दोस्ती की मिसाल पेश की। संस्था प्रमुख का कहना है दोस्ती वो नहीं जो सोशल मीडिया तक सीमित हो सच्चा दोस्त वही है जो समय पड़ने पर अपना खून तक दे सके।

किसान और किसानी-प्रोत्साहन तथा परिणाम विषयक संवाद कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों का किया सम्मान

आधुनिक तकनीक से बदल रही खेती की तस्वीर: सीएम साय

रायपुर। खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का आधार है। छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधिकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग, कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी

रायपुर में आयोजित %किसान और किसानी-प्रोत्साहन तथा परिणाम% विषयक संवाद कार्यक्रम में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को उत्कृष्ट खेती, नवाचार और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों, उद्योग जगत तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका जीवन स्वयं खेती-किसानी से जुड़ा रहा है। किसान परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने बचपन से खेतों में



काम किया और खेती की कठिनाइयों तथा किसानों की आवश्यकताओं को निकट से देखा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में दिल्ली में रहने के दौरान भी वे नियमित रूप से अपने गांव और खेत की जानकारी लेते थे तथा गांव पहुंचने पर खेत अवश्य जाते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले

कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पहले किसान पूंजी के अभाव में साहूकारों या कर्ज पर निर्भर रहते थे, जबकि आज किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें समय पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किए जाने को किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि आज किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर केंसीसी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे खेती करना पहले की तुलना में अधिक सहज हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने

कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों से किए गए वादों को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान को खरीदी कर रही है। इसके साथ ही पूर्व में लॉबित दो वर्ष के बोनस का भी भुगतान किसानों को किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले खरीफ विपणन सीजन में राज्य के लगभग 25 लाख किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई।

प्रशासन की तत्परता से टले दो बाल विवाह

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने का अभियान लगातार प्रभावी परिणाम दे रहा है। सुकमा जिले में जिला प्रशासन की तत्परता और संवेदनशील पहल से दो बाल विवाह समय रस्ते रोक दिए गए। यह कार्रवाई कवासीपारा, फूलबगड़ी गाँव में मूसलाधार बारिश के बीच की गई।

चाइलड हेल्पलाइन 1098 से बाल विवाह की सूचना मिलते ही जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइलड लाइन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम तुरंत गाँव के लिए रवाना हुई। कठिन मौसम और बारिश के बावजूद टीम समय पर मौके पर पहुँची और दोनों बाल विवाह रूकवाने में सफल रही।



गाँव में विवाह की तैयारियों चल रही थीं। अधिकारियों ने स्थानीय परंपराओं का सम्मान करते हुए परिवारों से शांतिपूर्ण और संवेदनशील तरीके से बातचीत की। टीम ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी दी और बताया कि कम उम्र में विवाह से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर असर पड़ता है। प्रशासन की समझाइश का सकारात्मक परिणाम

सामने आया। दोनों परिवारों ने बाल विवाह स्थगित करने का निर्णय लिया। बालिकाओं ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखने और सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा जताई। पूरी कार्रवाई को पारदर्शी और वैधानिक बनाने के लिए मौके पर पंचनामा और घोषणा-पत्र तैयार कराया गया। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो सके।